04 - निजी कंपनियों से बिजली खरीदी के मायने

05 - दण्डक्रम परायण का आधुनिक विज्ञान के नजरिए से विश्लेषण

A Daily News Magazine

इंदौर

मंगलवार, 09 दिसंबर, 2025

06 - बिना टैक्स जमा किए लोग मुफ्त में पी रहे नपा का पानी

07 - 79वां होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 74, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

'इंडिगो' का संकट खराब मैनेजमेंट का नतीजा है....

वीर सांघवी

इंडिगो, जिसे लंबे समय से भारतीय काबिलियत और बेहतरीन मैनेजमेंट की जीत माना जाता था, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इस संकट के तीन हिस्से हैं। दिल्ली और दूसरे शहरों के हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मची हुई है और आसमान में भी हालात बिगड़े हुए हैं। इस अफरा-तफरी की सबसे बड़ी वजह इंडिगो है, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसने 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। इनमें से कई कैंसिल आखिरी समय में की गई हैं। यात्री हवाई अड्डे तक जाते हैं, कई घंटों तक लगातार देरी झेलते हैं और फिर देर रात उन्हें बताया जाता है कि उनकी उड़ान रद्द हो गई है और उन्हें वापस घर जाना पड़ेगा।

हालात इससे भी बदतर हैं। कई बार स्थिति इतनी अव्यवस्थित होती है कि यात्रियों को उनका चेक-इन किया हुआ सामान भी वापस नहीं मिल पाता और हजारों सूटकेस हवाई अड्डों पर जमा हो रहे हैं। देरी सिर्फ असुविधा ही नहीं दे रही, बल्कि यात्रियों को इसलिए और भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि इंडिगो के पास जानकारी देने के लिए पर्याप्त ग्राउंड स्टाफ नहीं है। और जब कोई यात्री किसी स्टाफ से बात करने में सफल भी हो जाता है, तो पता चलता है कि वह कर्मचारी भी उतना ही अनजान है जितना यात्री।

जैसे-जैसे देरी और कैंसिलेशन बढ़े हैं, यात्रियों की परेशानी हद से आगे निकल गई है। लोग अपनी खुद की शादियां मिस कर रहे हैं। कई कार्यक्रम, जो महीनों पहले तय किए गए थे, रद्द करने पड़े हैं क्योंकि उड़ानें उपलब्ध नहीं हैं। इससे भी बुरा यह कि इंडिगो की अव्यवस्था ऐसी है कि कोई यह नहीं बता पा रहा कि अगले दिन उड़ानें चलेंगी या नहीं। या उसके बाद भी।

हवाई अड्डों पर अव्यवस्था ऐसी चीज है जिसका सामना यात्रियों को कभी न कभी करना पड़ता है। लेकिन आमतौर पर इसकी वजह वे घटनाएं होती हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, जैसे चक्रवात, कोई बड़ा हादसा या तकनीकी खराबी। इस बार वजह बहुत साफ और चिंताजनक है: प्रबंधन की विफलता।

आप सोच सकते हैं कि इंडिगो, जिसे भारतीय कुशलता और बेहतरीन प्रबंधन का उदाहरण माना जाता था, इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है? और लोग यह भी पूछ रहे हैं कि एयर इंडिया, जिसे हमेशा बुरा-भला कहा जाता था, वही हालात होने के बावजूद कैसे इतनी अच्छी तरह काम कर रहा है?

इस संकट के तीन हिस्से हैं, तो आइए उन्हें एक-एक करके समझते हैं। पहला हिस्सा पायलटों का है। लंबे समय तक पायलटों को इंडियन एविएशन का 'बैड बॉयज़' माना जाता था। शायद इसलिए कि उनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा थी, और व्यवहार सबसे खराब। वे आखिरी समय में जानबूझकर बीमार होने की सूचना देते थे जिससे शेड्यूल बिगड़ जाते थे। वे हमेशा ज्यादा वेतन और आसान कामकाजी शर्तों की मांग करते थे, यात्रियों के बारे में सोचे बिना। मेरे लिए लास्ट पॉइंट 1990 के दशक में आया जब बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पूरा भारत जल रहा था। इसी समय पायलट्स ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया।

लेकिन अब सब बदल गया है। भले ही पुरानी छवि आज भी बनी हुई है, लेकिन यह पीढ़ी अधिक जिम्मेदार है, और कई लोग कहते हैं कि आज वे पीड़ित भी। उदाहरण के तौर पर, जब टाटा ने नई एयर इंडिया बनाने के लिए पुरानी कंपनियों (जिनमें इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के गुट थे) को विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मिलाया, तो उम्मीद थी कि पायलट जोरदार विरोध करेंगे। लेकिन वे सहयोगी और समझदार निकले।

इस हफ्ते की अफरा-तफरी का दोष पायलटों पर लगाया जा रहा है, जबकि वे दोषी नहीं हैं। DGCA ने एयरलाइंस से बातचीत करके पायलटों के फ्लाइट ड्यूटी घंटे बदले और उड़ानों के बीच ज्यादा आराम का समय देना अनिवार्य किया। अगर आप अपने पायलटों को लगातार काम में झोंकते हैं, जैसा कि इंडिगो करता है, तो यह लंबा आराम समय पायलटों की कमी पैदा कर देता है।

एयरलाइंस को इन नए नियमों के लिए महीनों पहले तैयारी करने का समय दिया गया था। कुछ कंपनियों ने, जैसे एयर इंडिया ने, समय रहते बदलाव किए, इसलिए उसकी उड़ानों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। यह हमें संकट के दूसरे हिस्से की ओर ले जाता है: एयरलाइंस। इंडिगो ने माफी मांगते हुए कहा है कि वह पायलटों की नई स्थिति के लिए ठीक से तैयार नहीं हो पाया।

लेकिन क्या यह सच में ऐसा ही है? एयरलाइन उद्योग से जुड़े कई लोगों को संदेह है कि इंडिगो इस अफरा-तफरी से पूरी तरह दुखी नहीं है। पहले के जमाने में, पायलट त्योहारों के मौसम में हड़ताल की धमकी देते थे। एयरलाइन प्रबंधन और सरकार घबरा जाते थे और उनकी मांगें मान लेते थे। कुछ वैसा ही यहां भी हुआ है। जैसे-जैसे अराजकता बढ़ी, सरकार ने घबराकर नए नियम वापस ले लिए (फिलहाल के लिए)। और इस तरह इंडिगो को वह मिल गया जो वह चाहता था। अब सब कुछ पहले की तरह चल रहा है।

अब तीसरे हिस्से पर आते हैं: सरकार। क्या सरकार को खेल लिया गया है? क्या उसे पता नहीं था कि इंडिगो ने नए नियमों के हिसाब से पर्याप्त पायलट नहीं रखे हैं? क्या DGCA जैसी संस्थाएं इसकी निगरानी नहीं करतीं?

और वैसे भी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का काम इंडियन पैसेंजर का ख्याल रखना है, न कि इंडियन एयरलाइन मालिक का। इस इंसान की बनाई हुई मुसीबत में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। क्या एयरलाइंस को उन्हें अच्छा-खासा मुआवज़ा नहीं देना चाहिए? क्या एयरलाइन पर खुद जुर्माना नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसने उन यात्रियों को ले जाने के लिए ज़रूरी पायलटों की संख्या की परवाह नहीं की, जिनसे उसने पहले ही पैसे ले लिए थे?

अभी शुरुआती दिन हैं, और हालात सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब यह सब शांत हो जाएगा, तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को यह साबित करना होगा कि वह अपने काम के लिए सक्षम हैं और भारतीय लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं।

(दि प्रिंट में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

कोई वादे वफ़ा किया होता
मिलने का फैसला किया होता
बेवफाई तो हर किसी ने की
तुमने कुछ तो नया किया होता
साथ होते, जो साथ रहने का
वक्त पर फैसला किया होता
दुख समझते मेरा, अगर तुमने
रात भर रतजगा किया होता
काश होता तेरी तरह मैने
इश्क़ इक दूसरा किया होता
मंज़िलें कब की मिल गई होती
तय अगर रास्ता किया होता।

– अनवर कुरैशी

इंडिगो संकट- 7वें दिन 500+ फ्लाइट कैंसिल

● राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री बोले- सख्त एक्शन लेंगे ● 827 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए, 4500 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकीं हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं।

एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थीं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा- हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इंडिगो ने हालिया उड़ान संकट के दौरान अब तक 827 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए हैं। इसके साथ ही 4500 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया है।

लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा

जिन्ना की वजह से नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा : पीएम

● कांग्रेस ने वंदे मातरम् के टुकड़े किए

● नेहरू ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने एक घंटे की स्पीच में कहा, वंदे मातरम् अंग्रेजों को करारा जवाब था, ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था।

पीएम ने कहा, उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। वंदे मातरम् के साथ विश्वासघात क्यों हुआ। वो कौन सी ताकत थी, जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी।

● **60 मिनट के भाषण में 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र-** पीएम मोदी ने एक घंटे की स्पीच में वंदे मातरम् 121 बार, देश 50, भारत 35, अंग्रेज 34, बंगाल 17, कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। उन्होंने वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार, नेहरू 7 बार, महात्मा गांधी 6 बार, मुस्लिम लीग 5 बार, जिन्ना 3 बार, संविधान 3 बार, मुसलमान 2 बार, तुष्टिकरण 3 बार कहा।

● **जिन्ना के सामने झुके नेहरू, मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे -** जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जबाब देते, उसकी निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ।

सीएम ने खजुराहो में राजस्व विभाग की समीक्षा की, 21 से भोपाल में दौड़ेगी मेट्रो

मेट्रोपॉलिटन सिटी के दृष्टिगत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को उद्योग जगत के बीच करें प्रचारित : मुख्यमंत्री

खजुराहो/भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमएसएमई विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के दृष्टिगत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को उद्योग जगत के बीच इस तरह से प्रचारित और प्रस्तुत करें, जिससे अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हों तथा व्यापक निवेश और रोजगार सृजित हो सकें। उन्होंने उद्योग वर्ष के समापन पर इस माह के अंत तक ग्वालियर में लगभग 2 लाख करोड़ निवेश वाली इकाइयों के भूमिपूजन औद्योगिक भूखंड आवंटन, शुभारंभ आदि का व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एमएसएमई के पंजीकरण में जबरदस्त 31 प्रतिशत की ग्रोथ पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे पिछले दो वर्ष में छोटे उद्योगों के लिए राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए शानदार वातावरण का उदाहरण बताया। उन्होंने फूड पार्क सहित अन्य ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को भी

एमएसएमई से जोड़ने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को खजुराहो में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गत 2 वर्ष के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। एमएसएमई मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विगत दो वर्ष में मध्यप्रदेश में एमएसएमई और स्टार्टअप के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। प्रदेश में इस अवधि में कई लाख करोड़ का निवेश आया है और नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और शुभारंभ हुआ है। एमएसएमई इकाइयों को 2780 करोड़ की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने 2019 से उद्यमों के लिए लंबित प्रोत्साहन राशि के संपूर्ण भुगतान को ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योग वर्ष के समापन पर यह विभाग की जिम्मेदारी है कि पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के साथ इन उपलब्धियों का मीडिया को भी मौके पर निरीक्षण कराए, जिससे निवेश और रोजगार में हुए कार्य पूरे देश में प्रचारित हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल सहित बड़े शहरों में फ्लैटेड इंडस्ट्रियल पार्क के विकास कार्यों में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को जोड़ें, जिससे मितव्ययता बनी रहे। प्रदेश में एमएसएमई एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार, औद्योगिक संरचना के विकास तथा आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

औद्योगिक अधोसंरचना का विस्तार

समीक्षा बैठक में बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। कुल 1,240 भूखंड उद्यमियों को उपलब्ध कराए गए, 13 औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और 14 नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में 31 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कार्य प्रगति पर है। निजी भूमि पर स्वीकृत 30 औद्योगिक क्षेत्रों में से 12 का विकास कार्य पूर्ण हुआ है। विभाग द्वारा पहली बार गोविंदपुरा, भोपाल में फ्लैटेड इंडस्ट्रियल पार्क का विकास कर नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया है।

वित्तीय समावेशन एवं उद्यम क्रांति योजना

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 15,838 युवाओं को लाभान्वित किया गया और 1,087.27 करोड़ रूपये की ऋण राशि वितरित की गई। प्रदेश की साख योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 2,45,038 करोड़ रूपये के विरुद्ध सितम्बर 2025 तक 1,93,872 करोड़ रूपये वितरित किए गए, जो पिछले दो वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। इससे एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय उपलब्धता और उद्यमिता को मजबूती मिली है।

कफ सिरप मामले में योगी सरकार ने एसआईटी बनाई

डिप्टी सीएम ने कहा- चाहे नेता हो, सब नपेंगे

लखनऊ (एजेंसी)। कफ सिरप मामले में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद,एफएसडीए सचिव रोशन जैकब और डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोशन जैकब ने कहा- कोडीन कफ सिरप मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा- कोडीन कफ सिरप का इस्तेमाल बीमारी के लिए नहीं, बल्कि नशे के लिए कराया जा रहा है। वहीं जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कफ सिरप मामले में जो दोषी होगा सब नपेंगे, चाहे नेता हो या कोई भी।

चिकन शॉप में रोटी बनाते वक्त तंदूर में थूका

● दुकानदार आधी रात में करनाल से यूपी भागा, सामान भी समेटा

करनाल (एजेंसी)। हरियाणा के करनाल में चिकन शॉप में रोटियों पर थूकने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद हो गया। वीडियो में तंदूर पर काम करने वाले युवक रोटियों में थूकता हुआ दिख रहा है। कई दिन दुकान बंद रही। 6 दिसंबर की रात मालिक ने ट्रक में सामान लादकर पूरी दुकान खाली कर दी और उत्तर प्रदेश चला गया। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने विरोध जताते हुए सिटी थाना में शिकायत दी।

80 की स्पीड में कार ने 6 को उड़ाया

● पटना में गाड़ी के पहिए से कुचलकर एक की मौत, बचने के लिए लोगों को रौंदता गया

दानापुर, पटना (एजेंसी)। पटना में एक बेकाबू कार ने 80 की स्पीड में 6 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। 5 लोग घायल हैं। मृतक की पहचान चांसी राय (60) के रूप में हुई है। यह घटना दानापुर थाना क्षेत्र के गोला पर झखड़ी महादेव रोड पर हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सबसे पहले कार ने रॉन्ग साइड में घुसकर 4 लोगों को उड़ाया।

सिद्धारमैया को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

● 2023 में वरुणा सीट से उनके चुनाव पर उठे सवालों पर मांगा जवाब

नईदिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 2023 की वरुणा सीट से हुई जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में मुफ्त बिजली, मुफ्त अनाज, बेरोजगारों को भत्ता, महिलाओं को आर्थिक मदद और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी कई योजनाएं देने का वादा किया था। याचिका के मुताबिक ऐसे वादे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हैं और इन्हें चुनावी गलत आचरण माना जाना चाहिए।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 27 °c
न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ मंगलवार, 09 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला

नोट गिनने की मशीन बुलाई, 93 लाख ऑनलाइन मिले 6 दिसबर को मुर्शिदाबाद में नींव रखी थी

मुर्शिदाबाद (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव

रखी। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। अब इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का एक वीडियो सामने आया है। हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी।

'प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं' कहने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

- सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा- ऐसी भाषा न बोलें, जो पीड़िता को डरा दे

प्रयागराज (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट अब देशभर के हाईकोर्ट के लिए एक व्यापक गाइडलाइन बनाने जा रही है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले पर बेहद सख्त टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि 'पायजामा का नाड़ा तोड़ना

और स्तनों को पकड़ना रेप के प्रयास के आरोप के लिए पर्याप्त नहीं है।' सुप्रीम कोर्ट ने रेप और यौन अपराध के मामलों में दिए जा रहे विवादित और महिला-विरोधी आदेशों पर गंभीर चिंता जताई। कहा, हम सभी हाईकोर्ट के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी टिप्पणियां पीड़ितों पर चिलिंग इफेक्ट यानी भयावह प्रभाव डालती हैं। कई बार शिकायत वापस लेने जैसा दबाव भी पैदा करती हैं। सीजेआई ने स्पष्ट शब्दों में कहा- अदालतें को, विशेषकर हाईकोर्ट को, फैसले लिखते समय और सुनवाई के दौरान ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों से हर हाल में बचना चाहिए।

कानपुर में युवक को नंगा कर पीटा, जूता चटाया

2 मिनट में 25 लात-घूंसे मारे, पैर छूकर माफी मंगवाई; 3 अरेस्ट

कानपुर (एजेंसी)। कानपुर में भूमाफिया के बेटे और उसके दोस्तों ने एक युवक को लात-घूंसों से जमकर पीटा। करीब 2 मिनट के वीडियो में आरोपियों ने युवक

को 25 लात-घूंसे मारे। फिर नंगा कर उसे जूता चटवाया। उसके चेहरे पर रगड़ा। इसके बाद आरोपियों ने अपने पैर छुआए। हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है।

प्रियंका गांधी का सवाल: वंदे मातरम् पर आज बहस क्यों

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर जारी चर्चा में प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है। देश के लोगों के दिल में बसा है।

75 साल से ये देश में है। आज इस पर बहस की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि मोदीजी बंगाल का चुनाव आ रहा। जिन्होंने स्वतंत्रता की आजादी लड़ी, सरकार उन पर नए आरोप लादना चाहती है। मैं कहूं- मोदी जी अब वह पीएम नहीं रहे जो पहले थे।

सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, जिस वंदे मातरम् ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं।

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लोकसभा में पेश

ऑफिस टाइम के बाद काम कराने पर देना होगा फुल ओवरटाइम पैसा...और बॉस भी नहीं चला पाएगा डंडा

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में हाल ही में 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' नाम का एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया है, जिसका मकसद कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद कार्य से जुड़े कॉल्स या ईमेल का जवाब देने के लिये कानूनी रूप से बाध्य होने से बचाना है, ताकि वर्क लाइफ बैलेंस बनाया जा सके। इसमें काम के घंटे पूरे होने पर ओवरटाइम पैसे देने का भी प्रावधान है। लोकसभा मे यह बिल एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पेश किया।

कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना- इस निजी विधेयक में एक कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है, जो 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में राइट टू डिस्कनेक्ट के अधिकार को लागू करने, आधारभूत अध्ययन करने और कार्य समय के बाद काम से संबंधित शर्तों पर चर्चा करने का कार्य करेगा।

- **ज्यादा समय तक काम करवाने पर देना होगा ओवरटाइम-** विधेयक के अनुसार, कर्मचारी जो निर्धारित समय के बाद संवाद करने से इनकार करते हैं, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। यदि उन्हें निर्धारित समय से अधिक काम दिया जाता है तो नियोक्ता को ओवरटाइम वेतन का भुगतान करना होगा।
- **डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स बनाए जाएं-** विधेयक में टेलीप्रेशर, तनाव और इन्फो-ओबेसिटी जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिये परामर्श सेवाओं और डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स बनाए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- **फ्रांस, पुर्तगाल-ऑस्ट्रेलिया में है लागू-** फ्रांस, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले ही इस प्रकार के अधिकार लागू कर दिए हैं, जो कर्मचारी कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाते हैं। भारत के इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी विधेयक के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती है।

राजधानी में वायु प्रदूषण का कहर !

- बढ़ते स्मॉग और बदलते तापमान से हालात और गंभीर, सांस लेना हुआ मुश्किल

नईदिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार (8 दिसंबर) को भी स्मॉग की मोटी परत छाई रही। हवा इतनी खराब रही कि लोगों को सुबह से ही चुभन, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन का सामना करना पड़ा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 308 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है और सेहत पर सीधा असर डालने वाला स्तर माना जाता है। दिल्ली के 29 स्टेशनों ने दिखाई 'बहुत खराब' हवा समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के 29 प्रदूषण निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को 'बहुत खराब' बताया। सोमवार सुबह 10 बजे औसत एक्यूआई 302 दर्ज हुआ और 26 स्टेशनों ने 'बहुत खराब' स्तर रिकॉर्ड किया। दिल्ली की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी परिवहन क्षेत्र की रही, जिसका योगदान 16.5 प्रतिशत था।

लाड़ली बहना योजना 31वीं किस्त

सीएम मोहन यादव आज छतरपुर में करेंगे 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर

भोपाल (नप्र)। सीएम डॉ. यादव मंगलवार को छतरपुर जिले के राजनगर में लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में सीएम प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में दिसंबर महीने की 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे।

छतरपुर जिले के राजनगर में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। यह कार्यक्रम सती की मढ़िया परिसर में होगा। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश की लाड़ली बहनों से संवाद करेंगे और योजना से जुड़ी जरूरी बातों को साझा करेंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव 9 दिसंबर को लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर वे राज्यभर की 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में दिसंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त ट्रांसफर करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद है।

31 किस्त का इंतजार- बीते नवंबर में इस योजना के तहत 1 करोड़ 26 लाख 36 हजार से अधिक लाभार्थियों को कुल 1857 करोड़ रुपये उनके खातों में भेजे गए थे। अब महिलाएं दिसंबर की 31वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं, जो इस कार्यक्रम के साथ पूरी हो जाएगी। लाड़ली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

छतरपुर में खाद के लिए 4 जगहों पर चक्काजाम

किसान रात भर से कतार में लगे थे ; खजुराहो जा रहे मंत्रियों की आवाजाही भी रही प्रभावित

छतरपुर (नप्र)। खजुराहो में मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठक चल रही है। इससे पहले खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। सोमवार को बमीठा थाना क्षेत्र में हजारों किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-39 पर जाम लगा दिया। इससे खजुराहो जा रहे मंत्रियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।

दरअसल, खजुराहो में बैठक की तैयारियां चल रही थीं, वहीं पास की सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। हरपालपुर में भी खाद की कमी से परेशान किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-76 पर थाने के सामने जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन किसानों को समझाने में जुटा रहा।

किसान देर रात से मंडी में लाइन में खड़े दिखे- अधिकारियों के अनुसार, सोमवार सुबह से 1300 से ज्यादा टोकन बांटे जा चुके थे। किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की सटई रोड स्थित मंडी में भी किसान देर रात से लाइन में खड़े दिखे। पिछले बुधवार को इसी मंडी में हजारों किसानों की भीड़ के कारण व्यवस्था बिगड़ गई थी और किसानों ने सड़क जाम कर दी थी।

तहसीलदार के थप्पड़ मारने से बढ़ा था विवाद- सौरा मंडल की तहसीलदार ऋतु सिंघई द्वारा छात्रा को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आने से विवाद और बढ़ गया था। इसके बाद ईसानगर तहसीलदार आकाश नीरज और एसडीएम अखिल राठौर पर भी महिलाओं से बदसलूकी और झूमाझटकी के आरोप लगे थे। इस घटना को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ऋतु सिंघई की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

महंगी खाद बेचने की शिकायत भी सामने आ रही- हालांकि, अभी तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लवकुशनगर में भी खाद वितरण केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। बुवाई का समय होने के कारण किसान खाद के लिए परेशान हैं, वहीं बाजार में डीएपी 1900 से 2000 रुपए और यूरिया के 500 से 600 रुपए प्रति बोरी ब्लैक में बिकने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

उत्तराखंड में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट

- केदारनाथ में तापमान माइनस 17 डिग्री
- इंदौर में पारा 5.7 डिग्री, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा
- अयोध्या का तापमान 5.5 डिग्री पहुंचा; राजस्थान में ओस की बूंदें जमीं

नई दिल्ली /देहरादून/ भोपाल/राजस्थान/लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर भारत में शीतलहर का असर जारी है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में रविवार को न्यूनतम तापमान तीन से सात डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज यानी सोमवार दोपहर को भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ पूरी तरह से सफेद नजर आ रहे हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी जारी है, जिससे आज रात से पूरे प्रदेशभर में ठंड बढ़ जाएगी और कल से पहाड़ी इलाकों में पाला गिरेगा।

मप्र के ज्यादातर शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। यूपी के 20 जिलों में सोमवार को सीजन पहली बार घना कोहरा था। वहीं चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी किया।

बिहार में सर्दी लगातार बढ़ रही है। राज्य के शेखपुरा जिले में सबसे कम तापमान, 8.4 डिग्री दर्ज किया गया।

गोवा क्लब अग्निकांड-में अब तक क्लब मैनेजर सहित 5 गिरफ्तार

- 25 मौतें, इनमें 20 कर्मचारी थे
- सीएम बोले- पटाखे फोड़ने से आग लगी, 3 अधिकारी सस्पेंड
- पुलिस का मालिकों को लुकआउट नोटिस

पणजी (एजेंसी)। गोवा के नाइट क्लब में रविवार रात आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने क्लब चेन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गोवा पुलिस ने क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। गोवा-नाइट क्लब में आग, 25 मौतें, इनमें 20 कर्मचारी थे। सीएम बोले- पटाखे फोड़ने से आग लगी थी। क्लब मैनेजर सहित 4 गिरफ्तार, 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं।

आरोप है कि बिना जरूरी दस्तावेजों और लाइसेंस के क्लब चलाया जा रहा था। इधर, सोमवार को मामले में पांचवी गिरफ्तारी की गई। दिल्ली से क्लब के ऑपरेशन मैनेजर भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक पटाखे से आग लगने की बात सामने आई है।

रक्षामंत्री राजनाथ ने बीआरओ के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया

कहा- ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने अहम भूमिका निभाई

लेह (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे बीआरओ और केंद्र के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।

राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छी सड़कें, रियल टाइम कम्युनिकेशन, सेटेलाइट स्पोर्ट, सर्विलांस नेटवर्क व लाजिस्टिक स्पोर्ट से देश के सीमाओं पर आज हमारे सैनिक मजबूती के साथ खड़े हैं। आपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने लद्दाख में दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड पर बनी 920 मीटर लंबी श्योक टनल, गलवान मेमोरियल, कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों के 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए।

पत्नी ने हाथ पकड़े, बॉयफ्रेंड ने पति का गला दबाया, मौत

कत्ल के बाद दोस्त के साथ चंडीगढ़ पहुंचा प्रेमी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब के फरीदकोट में पति की हत्या के मामले में पुलिस जांच में नया खुलासा हुआ है। जहर का असर नहीं हुआ तो पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है।

पुलिस के मुताबिक पत्नी रूपिंदर कौर ने पति गुरविंदर सिंह के हाथ पकड़े और बॉयफ्रेंड ने पीछे से उसे बांह से जकड़कर उसका गला दबा दिया। इस दौरान पति तड़पते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा। लेकिन रूपिंदर ने नहीं छोड़ा। चूंकि पत्नी उसे पहले ही जहर दे चुकी थी, जिसका कुछ असर पति पर था, इस वजह से वह ज्यादा जोर नहीं लगा सका। पोस्टमॉर्टम से भी पता चला कि गुरविंदर की सांस बंद होने से मौत हुई थी। इसके अलावा गुरविंदर से पत्नी रूपिंदर और बॉयफ्रेंड हरकंवल ने

मारपीट भी की थी। पति के शरीर पर चोटों के 10 से 12 निशान भी मिले हैं। कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ चंडीगढ़ आ गया था।

पिता को पकड़ा तो बॉयफ्रेंड ने सरेंडर किया- पुलिस के मुताबिक फरीदकोट के गांव सुखनवाला में हुए इस कत्ल में शामिल बॉयफ्रेंड हरकंवल अपने डबवाली के रहने वाले दोस्त विश्वदीप के साथ सीधे चंडीगढ़ भाग आया। यहां से उसकी प्लानिंग मुंबई जाने की थी। जैसे ही उसे घर से पता चला कि पुलिस घर पहुंच गई है और उसके पिता को साथ ले गई है, तब जाकर उसने अदालत में सरेंडर किया।

पत्नी के खिलाफ पहला क्लू, कपड़ों की तह नहीं खुली थी

थाना सदर फरीदकोट प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पत्नी ने लूट का शोर मचाते हुए पति की हत्या की बात कही थी। इसके लिए घर का सामान भी बिखेर दिया था। हालांकि जब वे उनके बेडरूम में पहुंचे तो देखा कि कपड़े जमीन पर तो गिरे हैं लेकिन उनकी तह नहीं खुली है। अलमारी के सिर्फ दराज खुले हैं।

ऐसे में उन्हें शक हो गया। यहीं से जांच की पूरी सुई पत्नी रूपिंदर कौर की तरफ घूम गई। उन्होंने यह भी कहा कि वह कत्ल न करने के बारे में पिता की झूठी कसम भी खाती रही। राजेश कुमार ने कहा कि पूरे मामले की साइंटिफिक ढंग से जांच की जा रही है। गुरविंदर सिंह के घर पर हत्या के बाद रुपिंदर कौर ने जमीन पर कपड़े बिखेर दिए थे, मगर वह पूरी तरह से बिखरे नहीं थे। इसलिए पुलिस को उस पर शक हुआ।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में इंदौर जिले का रिकॉर्ड, 'एसआईआर' लक्ष्य पूरा

जिले में मतदान केंद्रों की संख्या में भी बड़ा विस्तार संख्या 3210

इंदौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में इंदौर जिले द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने की घोषणा की गई। बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि की सराहना की और कहा कि इंदौर जिला टीमवर्क का उत्कृष्ट उदाहरण है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवजीवन विजय पवार,सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत

श्रीवास्तव, मुख्य प्रशिक्षक आर.के. पांडे सहित कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। कलेक्टर वर्मा ने समयसीमा से पूर्व लक्ष्य पूर्ण करने पर सभी अधिकारियों और दलों के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में लगभग 6 प्रतिशत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग को प्राथमिकता पर किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही बीएलओ और बीएलए की संयुक्त बैठक होगी। अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस जारी कर दस्तावेजों के आधार पर दावा-आपत्ति प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। जिले में मतदान केंद्रों की संख्या में भी बड़ा विस्तार हुआ है। वर्तमान 2625 केंद्रों के साथ 585 नए प्रस्तावित केंद्रों को अनुमोदन मिल चुका है, जिसके बाद कुल संख्या बढ़कर 3210 मतदान केंद्र हो गई है।

राजनीतिक दलों ने जन सुविधा बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए,जिन पर प्रशासन ने सकारात्मक आश्वासन दिया। अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की कि अनमैप्ड या एसजीडी सूची में परिवर्तन हेतु वे शीघ्र दावा प्रस्तुत करें,ताकि आगामी चरण समय पर और पारदर्शिता के साथ पूर्ण हो सकें।

चूहों के भय से शास्त्री ब्रिज के एक तरफ

फुटपाथ पर नए पेवर ब्लॉक लगाने से पहले पेस्ट कंट्रोल कराया जाएगा

इंदौर। शास्त्री ब्रिज को चूहों से मुक्त करने का नगर निगम ने फैसला लिया। इस कारण ब्रिज के फुटपाथ उखाड़ कर चूहों को तलाशा जा रहा है। वहां नए पेवर ब्लॉक लगाने से पहले पेस्ट कंट्रोल किया जाएगा और जहां बिल नजर आएंगे, उन्हें भरा जाएगा। हाल ही में ब्रिज के एक हिस्से में अचानक गड्ढा हो गया था। इसके बाद ट्रैफिक रोक दिया गया। नगर निगम ने जीएसआईटीएस कॉलेज के विशेषज्ञों के साथ पूरे ब्रिज का दौरा किया, तो पाया कि ब्रिज के आसपास सैकड़ों की संख्या में चूहों के बिल है, इस वजह से ही गड्ढा हुआ। 72 साल पुराने शास्त्री ब्रिज के कई हिस्सों को चूहों ने कमजोर कर दिया।

कुछ हिस्सों में फुटपाथ और सड़क के बीच गैप भी आ गया। निगम के अफसरों ने आशंका जताई है कि चूहों के बिल के कारण कुछ हिस्सा खोखला भी हो गया है। इस वजह से अब ब्रिज के फुटपाथ के पुराने पेवर ब्लॉक

फुटपाथ खोद दिया, ढूंढ रहे चूहों के बिल

निकलवाए जा रहे है। फिर इन फुटपाथ पर नए पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले फुटपाथों की मिट्टी हटाकर चूहों के बिल भी खोजे जा रहे, ताकि चूहों से ब्रिज को मुक्त करवाया जाए। ब्रिज पर जहां गड्ढा हुआ वहां भी चूहों के बिल मिले थे। वहां दीवार बनाकर गड्ढा भर दिया गया।

विशेषज्ञों ने ब्रिज के फुटपाथ के ब्लॉक बदलने और पेस्ट कंट्रोल करने की भी सलाह दी थी। नगर निगम की समिति के प्रभारी ने कहा कि ब्रिज के एक तरफ के हिस्से के फुटपाथ निकाल दिए गए है। यहां पहले कच्ची जगह पर पेस्ट कंट्रोल किया जाएगा। फिर कांच के टुकड़े डाले जाएंगे, ताकि चूहे फिर बिल न बना सके। इसके अलावा गांधी प्रतिमा सर्कल पर भी काफी चूहों के बिल है, क्योंकि यहां लोग पंछियों को दाना डालते है। चूहों को भोजन आसानी से मिल जाता है। सर्कल से भी निगम चूहों के बिल हटाया जाएगा।

शास्त्री ब्रिज इंदौर का पहला ब्रिज है, जो शहर के दो हिस्सों को जोड़ता है। इसके नीचे से ट्रेन निकलती है। इस ब्रिज का लोकार्पण देश के पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री ने 1953 में किया था। तब यह ब्रिज दो लेन बनाया गया था। क्योंकि, तब शहर का ट्रैफिक कम रहता था। अब ट्रैफिक के हिसाब से इसके विस्तार की जरूरत है। लेकिन, फ़िलहाल नगर निगम इसे चूहों से मुक्त कराने के काम में लगा है।

करणी सेना का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल

इंदौर। अपने हक और अधिकारों की मांग को लेकर रविवार शाम इंदौर में श्री राजपूत करणी सेना ने प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह के नेतृत्व में जोरदार मशाल रैली निकाली। राजवाड़ा से शुरू हुई यह रैली रीगल स्थित गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में युवा, वरिष्ठजन और मातृ शक्ति ने शामिल होकर सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। कारी सैनिकों की मुख्य मांग यूपीएससी सहित अन्य उच्च परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग को उम्र व अटेम्प्ट की छूट देने की है। प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने कहा कि '10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण सवर्ण समाज को दिया गया था,लेकिन इसकी अनेक विसंगतियों के कारण वास्तविक पात्र लाभ से वंचित हैं।' इसी मुद्दे पर 26 अक्टूबर को उज्जैन से शुरू हुई राज्यव्यापी मशाल रैली का दूसरा चरण आज इंदौर में आयोजित किया गया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकार जब तक ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर कर आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत नहीं करती, तब तक करणी सेना तहसील और जिला स्तर पर लगातार रैलियां निकलती रहेगी।

इनोवा लेकर फरार होने वाला चोर गिरफ्तार

इंदौर। एरोड्रम थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से वाहन चोरी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर चुराई गई इनोवा कार बरामद कर सफलता हासिल की है। आरोपी पहले भी ऑनलाइन एड देखकर वाहन चोरी की वारदातें कर चुका है। मामले के अनुसार फरियादी प्रकाश मंडलिक ने अपनी इनोवा कार बिक्री के लिए फेसबुक पर विज्ञापन पोस्ट किया था। 1 दिसंबर को एक अज्ञात युवक टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर फरार हो गया। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने आरोपी अमित यादव निवासी विनोबा नगर को गिरफ्तार कर करीब 5 लाख रुपये मूल्य की चुराई गई कार बरामद की। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी वर्ष 2024 में ओएलएक्स पर विज्ञापन देखकर एक बाइक चोरी की वारदात में भी शामिल रहा है,जिस पर थाना अन्नपूर्णा में मामला दर्ज है।

मोहल्ला मीटिंग में सुरक्षा, जागरूकता पर फोकस

इंदौर। थाना लसूड़िया क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 स्थित शिव मार्तण्ड मंदिर परिसर में पुलिस द्वारा मोहल्ला मीटिंग एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों और पुलिस के बीच विश्वास व सहयोग को मजबूत करना तथा सुरक्षा, साइबर फ्रॉड और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चेताया गया। नागरिकों को अनजान कॉल, लिंक व संदेशों से दूर रहने, ओटीपी और पासवर्ड साझा न करने और किसी भी धोखाधड़ी पर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत करने की सलाह दी गई। नशे के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए युवाओं को खेल, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने, बीट पुलिसिंग व महिला सुरक्षा पहल की जानकारी साझा की गई। ट्रैफिक, सड़क सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई।

जैविक हाट में किसानों को बिक्री मंच

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा ने रविवार को ढक्कन वाला कुआँ स्थित ग्रामीण हाट बाजार में संचालित जैविक हाट विक्रय केंद्र का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों द्वारा जैविक विधि से तैयार किए गए विभिन्न कृषि व खाद्य उत्पादों को देखा और उनकी गुणवत्ता की प्रशंसा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निरंतर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत हर सप्ताह इस हाट बाजार में उन्हें अपने उत्पाद बेचने हेतु निर्धारित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे जैविक उत्पाद अपनाकर स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। आगामी 12, 13 एवं 14 दिसंबर को इसी हाट में विशेष जैविक मेला आयोजित होगा। कलेक्टर की पहल पर जिले में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष व्यवस्था लागू की जा रही हैं, जिसका लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिलने की उम्मीद है।

नकली बायो डीजल पंप सील किया

इंदौर। देपालपुर स्थित मे. प्राप्ति बायो डीजल पंप पर नकली बायोडीजल की बिक्री किए जाने का खुलासा होने पर खाद्य विभाग ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुँची विभागीय टीम ने पंप का निरीक्षण कर तत्काल उसे सील कर दिया। जांच के दौरान पंप पर बड़ी मात्रा में मानक-विरुद्ध, कम डेंसिटी वाला नकली बायोडीजल पाया गया। सहायक आपूर्ति अधिकारी शिव सुंदर व्यास, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अजय अस्थान और सर्वेश सिंह गामड़ की संयुक्त टीम ने पंप की जांच की। प्रारंभिक परीक्षण में डेंसिटी 900 से अधिक होने का मानक पाया जाना चाहिए था, जबकि मौके पर मात्र 821 डेंसिटी का मिश्रण मिला। इसके अलावा पंप संचालक द्वारा राज्य शासन की अधिकृत छह कंपनियों के बजाय अनाधिकृत सप्लायर से माल लेना भी सामने आया। कार्रवाई के दौरान कुल 17671 लीटर नकली बायोडीजल जब्त किया गया, जिसकी कीमत 15 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही। विभाग ने पंप, डिस्पेंसरी यूनिट और भूमिगत टैंकों को सील करते हुए बिक्री पूरी तरह बंद करवा दी। छह सैंपल अधिकृत लैब में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

दो दिनों के लिए मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया

मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ और ला नीना का प्रभाव

इंदौर। तेज सर्द हवाओं के चलते शहर में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन कई जिलों में कड़ी ठंड का अलर्ट जारी किया है। रविवार को दिन में कुछ राहत जरूर मिली और अधिकतम पारा 27 डिग्री रहा। तेज धूप की वजह से दो दिन से चल रही ठंडी हवाओं की चुभन भी कम लगी। वहीं शनिवार-रविवार रात के पारे में भी उछाल देखा गया और 2.2 डिग्री के उछाल के साथ पारा 8.4 पर आ गया।

शुक्रवार और शनिवार की रात प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया, जहां राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित कुल 26 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इंदौर में तो शुक्रवार और शनिवार की रात में पारा 6.2 डिग्री तक चला गया था, यह पिछले 10 साल में दिसंबर का सबसे कम तापमान है। करीब 14 दिनों के अंतराल के बाद प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर और कोल्ड डे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए अगले दो दिनों तक शीतलहर चलने का

अलर्ट जारी किया है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में चल रही ठंड का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। इसके चलते पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश हुई है। वहां से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश का रुख किया है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर और शहडोल में शीतलहर का प्रभाव रहा, जबकि इंदौर, सिवनी और बैतूल में दिन काफी ठंडा रहा।

सर्दी का कारण ला नीना – मौसम विभाग के अनुसार इस बार वैश्विक मौसम मॉडल पहले से ही ला नीना के सक्रिय होने का संकेत दे रहे थे। ला नीना की स्थिति में प्रशांत महासागर ठंडा हो जाता है, जिससे हवाएं और अधिक ठंडी होकर एशिया और भारत की तरफ दबाव के साथ आती हैं। यही कारण है कि नवंबर माह से ही मध्य भारत में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।

पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश

इस वर्ष उत्तर भारत के पहाड़ों पर सामान्य समय से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडक 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय रहने से हल्की बारिश या मावठा गिरने की संभावना भी बन रही है। बारिश होने पर तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की और गिरावट आ सकती है, जिससे इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे शहरों में दिन में भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी।

1.94 लाख मतदाताओं का 2003 का रिकॉर्ड नहीं, अब देने होंगे दस्तावेज

5 लाख 61 हजार 447 मतदाताओं का सत्यापन अभी नहीं हुआ

इंदौर। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं का पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। जिले में अब तक 28 लाख 67 हजार 294 मतदाताओं के फार्म भरे गए, जिनमें से 1 लाख 94 हजार 208 मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी। बताया गया कि इन मतदाताओं ने 2003 का रिकॉर्ड या पहचान संबंधी आवश्यक जानकारी दिए बिना ही फार्म जमा करा दिए थे। अब इन सभी मतदाताओं को एआरओ (सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने पर मतदाताओं को निर्धारित 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जमा कराना होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद एआरओ निर्णय लेंगे कि मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जाए या नहीं। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 23 लाख 5 हजार 881 मतदाताओं की उपस्थिति की पुष्टि हुई। लेकिन, 5 लाख 61 हजार 447 मतदाताओं का सत्यापन अभी नहीं हो पाया। इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। नाम हटाने से पहले जिला निर्वाचन कार्यालय इनका दोबारा सत्यापन करने जा रहा है।

फार्म लिए पर जमा नहीं – उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार ने बताया कि जिन 5.61 लाख मतदाताओं के फार्म नहीं मिले, उनका पुनः सत्यापन 11 दिसंबर तक कराया जाएगा। इनमें 2 लाख 70 हजार 264 मतदाता ऐसे हैं, जो घर पर नहीं मिले हैं। 2 लाख 4 हजार 250 मतदाता स्थाई रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गए। 41 हजार 595 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 26 हजार से अधिक लोग फार्म लेकर गए भी, लेकिन वापस जमा नहीं कराया।

यह रहेगी प्रक्रिया – 11 दिसंबर तक अनुपस्थित और संदिग्ध मतदाताओं का पुनः सत्यापन किया जाएगा। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

'सानंद' के मंच पर 'कुटुंब किर्तन' का सभी पांच समूहों के लिए मंचन

12 से 14 दिसंबर तक इस नाटक का मंचन किया जाएगा

इंदौर। 'सानंद न्यास' के पांच दर्शक समूहों के लिए नाटक 'कुटुंब किर्तन' का मंचन 12, 13 और 14 दिसंबर को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागृह खंडवा रोड इंदौर में होगा। सानंद न्यास के अध्यक्ष जयंत भिसे एवं मानद सचिव संजीव वावीकर ने बताया कि इस नाटक में अभिनेत्री वंदना गुप्ते एवं प्रसिद्ध अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे होंगे। 'सानंद' के मंच पर अभिनेत्री वंदना गुप्ते को लंबे अर्से के बाद देखने का अवसर मिलेगा। वंदना गुप्ते एक प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने रंगमंच, मराठी फिल्मों और टेलीविज़न में लंबे समय तक काम किया। उन्होंने रंगमंच से करियर शुरुआत की। बाद में मराठी फिल्मों और टीवी (मराठी व हिंदी दोनों) में काम किया है। आप विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा चुकी हैं। कॉमेडी, सामाजिक नाटक, मे अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं।

संकर्षण कऱ्हाडे एक लोकप्रिय मराठी टीवी अभिनेता और एंकर हैं। उन्होंने मला सासू हवी, माझी तुझी रेशीमगाठ, खुलता कळी खुलेना जैसी धारावाहिकों में विभिन्न भूमिकाएं के जरिए लोकप्रियता पायी है। आम्ही सारे खवय्ये, किचन कल्लाकार आदि कार्यक्रमों का संचालन भी किया। आपने झी उत्सव नात्यांचा पुरस्कार समारोह का संचालन और कॉमेडी रोल भी किया। गौरी प्रशांत दामले की संस्था प्रशांत दामले फॉउंडेशन निर्मित इस नाटक के कलाकार है संकर्षण कऱ्हाडे, तन्वी मुंडले, अमोल कुलकर्णी एवं वंदना गुप्ते। इसके लेखक संकर्षण कऱ्हाडे, नेपथ्य प्रदीप मुळ्ये, कथासूत्र विनोद रत्ना, निर्देशक अमेय दक्षिणदास, प्रकाश योजना किशोर इंगळे, संगीत अशोक पत्की, वेशभूषा श्वेता बापट और सूत्रधार अजय कासुर्डे हैं। तीन दिन में 5 बार होने वाले इस नाटक का मंचन 12 दिसंबर को मामा मुजूमदार समूह के लिए शाम 6.30 बजे, 13 दिसंबर को रामू भैय्या दाते समूह के लिए दोपहर 4 बजे और शाम 7.30 बजे राहुल बारपुते समूह के लिए होगा। इसी प्रकार 14 दिसंबर को वसंत समूह के लिए दोपहर 4 बजे और शाम 7.30 बजे मंचन बहार समूह के लिए होगा।

'इंडिगो' की तीन दिन में 100 उड़ानें निरस्त, यात्रियों ने ट्रेन और बस ढूंढी

पुणे-दिल्ली-मुंबई जाने के लिए ट्रेन और बसों का सहारा ले रहे

इंदौर। लगातार चौथे दिन दिल्ली-मुंबई जाने वाली इंडिगो की उड़ान निरस्त होने से यात्री परेशान हैं। दूसरी एयरलाइंस कंपनियों और निजी बस ऑपरेटरों की इससे चांदी हो रही है। दिल्ली-मुंबई जाने वाली बसों का किराया बढ़ गया है। इसके अलावा दूसरी एयरलाइंस कंपनियों का दिल्ली, मुंबई व अन्य शहरों के लिए जाने वाली उड़ानों की टिकट भी महंगे हो गए हैं। छोटे विमानों के संचालन में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन बड़े विमानों की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। इंदौर से हर दिन 90 से ज्यादा उड़ानें संचालित होती हैं। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा सबसे ज्यादा उड़ाने इंदौर से इंडिगो की हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उड़ानें इंदौर से है। तीन दिन में इंदौर से 100 से ज्यादा उड़ान निरस्त हो चुकी हैं। इंडिगो एयरलाइन क्रू मेंबर्स की कमी झेल रही है। इस कारण कंपनी की उड़ानें लगातार निरस्त हो रही हैं या देरी से संचालित हो रही हैं। लगातार आ रही परेशानी

को देखते हुए यात्रियों ने दूसरे विकल्पों को अपनाना शुरू कर दिया है। लोग दिल्ली-मुंबई जाने के लिए ट्रेन और बसों से जाना पसंद कर रहे हैं। ट्रेवल एजेंट नितिन विजयवर्गीय ने बताया कि उड़ानें निरस्त होने के कारण यात्रियों का दबाव ट्रेनों पर बढ़ रहा है। इंदौर से दिल्ली, मुंबई, व दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेनों में टिकट आसानी से कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं।

किराया पंद्रह से बीस हजार – इंडिगो की उड़ानें निरस्त होने के कारण दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। इंदौर से बड़े महानगरों के टिकट 20 से 25 हजार रुपये में मिल रहे है, जबकि सामान्य दिनों में किराया आठ से दस हजार रुपये तक होता है। सबसे ज्यादा किराया दिल्ली का बढ़ा हुआ है। इंदौर से सबसे ज्यादा दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ानें हैं। कई यात्रियों को दिल्ली से दूसरे शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेना होती है। इस कारण यात्रियों का दबाव सबसे ज्यादा दिल्ली के रूट पर है।

दिक्कत का कारण – डीजीसीए ने नए नियम लागू किए हैं। देश में सबसे ज्यादा उड़ान इंडिगो कंपनी संचालित करती है। इस कारण उसे स्टाफ की कमी और उड़ानों के ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद नियमों में बदलाव हुआ है। पहले पायलट छह लैंडिंग करते थे, लेकिन अब वे एक दिन में दो लैंडिग कर पाएंगे। इसके अलावा लंबी उड़ानों के बाद एक दिन का आराम उन्हें करना होगा। ड्यूटी का समय भी कम हुआ है।

दो लोग फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का शिकार हुए, बिक्री जारी

प्रशासन की सख्ती ढीली, प्रतिबंध लगाने का असर नहीं

इंदौर। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे। कई स्थानों पर इसकी बिक्री जारी है। रविवार शाम शहर में फिर दो हादसे हुए जिसमें चाइनीज मांझे ने दो को घायल कर दिया। रानीपुरा क्षेत्र के हाथीपाला में दोपहिया वाहन से शाम 7 बजे जा रहा युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, वह संभल पाता उससे पहले गर्दन में कट लग गया। रेहान पुत्र मकबूल खान निवासी साउथ तोड़ा अपने दोपहिया वाहन से घर जा रहा था, तभी डोर उसकी गर्दन पर आ गई। गनीमत रही कि इस घटना के 10 सेकंड पहले ही रेहान के पास किसी का फोन आया था, उसे देखने के चलते वाहन की गति धीमी कर ली थी। यदि तेज रफ्तार में वाहन होता तो अधिक चोट लग सकती थी। डोर लगने के बाद परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार चल रहा है। भाई जावेद ने बताया कि रेहान फर्नीचर बनाने का काम करता है। वह काम के बाद ही घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ है।

हमने थाने पर भी इसकी सूचना दे दी है। घटना के बाद से घायल युवक घबराया हुआ है, वह उस हादसे को भूल ही नहीं पा रहा है।

अंगूठे में लगा कट

इसी प्रकार खजराना क्षेत्र में रोबोट चौराहे पर एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसे चोट आई है। 27 वर्षीय जीवन पुत्र शिव निवासी सतवास पैदल जा रहा था। तभी पैर में चाइनीज मांझा आकर उलझ गया, जिससे पैर के अंगूठे में कट लग गया। चोट लगने के बाद खून निकलने लगा। राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। यहां से एमवाय भेजा गया है। सप्ताह भर पहले रविवार के दिन ही चाइनीज मांझे से तेजाजी नगर क्षेत्र में आठवीं के छात्र 16 वर्षीय गुलशन पुत्र रामकिशन की मौत हो गई थी। वह अपने भाई और दो दोस्तों के साथ रालामंडल घूमने गया था। लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। छात्र की जान जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं।

मांझे के शिकार हर साल

जनवरी 2025 में द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में चाइनीज डोर की चपेट में आने से 20 वर्षीय हिमांशु पुत्र संजय सोलंकी की मौत हो गई थी। वह दोस्त के साथ बाइक पर गैस की टंकी लेने जा रहा था। इस दौरान वह चाइनीज डोर की चपेट में आ गया था और उसकी गर्दन कट गई। 21 दिसंबर को रणजीत हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव पर्व में विकास वर्मा पत्नी रीना के साथ जा रहे थे। तभी छत्रीपुरा और महू नाका के बीच 12 भाई रोड पर एक पतंग कटकर आई। विकास के कान को छूते हुए चाइनीज मांझा पत्नी रीना की गर्दन पर आ गया। गर्दन कटते ही खून बहने लगा। एक जनवरी को पिता के लिए खाना लेकर जा रहे 15 वर्षीय मोहम्मद फैज के सिर पर जूनी इंदौर ब्रिज पर चाइनीज डोर आ लगी थी। फैज लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। उसने जैसे-तैसे मोबाइल निकालकर पिता को फोन लगाया। वे सब काम छोड़कर तत्काल बेटे के पास पहुंचे और उसका इलाज कराया।

संपादकीय

अब बंगाल में 'मंदिर-मस्जिद'...!

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में जिस तरह 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के अलग-अलग शिलान्यास हुए, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यह कि क्या पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव उस मंदिर मस्जिद मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जिसे देश के बाकी हिस्से में अब लगभग खत्म मान लिया गया था। दूसरे, इस पूरे खेल का राजनीतिक उद्देश्य क्या है और तीसरे, इस खेल के पीछे कौन है? इसके जरिए किसको शह और मात दी जा रही है? पश्चिम बंगाल डेढ़ दशक से तृणमूल कांग्रेस की जुझारू नेता ममता बैनर्जी का गढ़ रहा है। ममता ने पहले राज्य में कम्युनिस्टों का मजूबत गढ़ ध्वस्त किया और अब वो भगवा ध्वज धारी भाजपा से लड़ रही हैं। ममता को राज्य की 30 फीसदी मुस्लिम आबादी का खुला समर्थन मिलता रहा है और बाकी हिंदू आबादी का वोट बंटने से ममता तीन चुनाव लगातार जीत रही हैं और चौथे विस चुनाव में भी उन्हें हराना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल है। मुर्शिदाबाद में तथाकथित बाबरी मस्जिद का शिलान्यास क्या राजनीतिक रंग दिखाएगा, इसे समझना जरूरी है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास बाबरी ध्वंस के दिन 6 दिसंबर को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मौलवियों की मौजूदगी में फीता काटकर किया। उन्होंने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। उसके बाद टीएमसी ने कबीर के बयान से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन कबीर अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने लोगों से ईंटें लेकर शिलान्यास स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया। उनकी अपील पर करीब दो लाख लोग ईंटे लेकर पहुंचे। और पुलिस यह सब होने देती रही। कबीर ने कहा कि यह बाबर के नाम पर यह भव्य मस्जिद करीब 3 सौ करोड़ रू. की लागत से बनेगी। दूसरी तरफ स्थारनीय भाजपा नेता सखारोव सरकार और उनके सहयोगियों ने मुर्शिदाबाद के पास बहरामपुर में अयोध्या की तर्ज पर नया राम मंदिर बनाने के लिए भूमिपूजन और शिला प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा कि यह शिला प्रतिष्ठा राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर की गई है। देश में कहीं भी किसी अविवादित जमीन पर धार्मिक स्थल का निर्माण कोई भी कर सकता है। लेकिन कबीर के मामले में पेंच यह है कि मस्जिद का नाम आक्रांता बाबर के नाम पर रखा जा रहा है। इस बीच हुमायूं कबीर ने टीएमसी से निलंबित होकर अपनी नई पार्टी बनाने और 153 सीटों पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर विस चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे नई खलबली है। भाजपा का आरोप है कि यह सब ममता का ही खेला है। ताकि वो अपना मुस्लिम वोट बैंक अटूट रख सकें। कबीर को निलंबित करना दिखावा है। जल्द ही उनका निलंबन खत्म कर दिया जाएगा। जबकि टीमएसी का मानना है कि इसके पीछे भाजपा की चाल है, जो राज्य में सीधा हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण कराना चाहती है, जो कि असंभव है। एक थ्योरी यह भी है कि हुमायूं कबीर को आगे कर ममता बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन औवेसी की एंट्री को झटका दिया है। वैसे कबीर ने अगर सचमुच अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा तो ममता के मुस्लिम वोट बैंक में तगड़ी सेंध लग सकती है। आगे क्या होगा, यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस बार बंगाल में अन्य मुद्दों के बजाए साम्प्रदायिक मुद्दे ही ज्यादा हावी होंगे, ऐसा लग रहा है। ममता बैनर्जी ने यूं तो राज्य में बंगाली अस्मिता के साथ साथ एसआईआर और एनआरसी को भी मुद्दा बनाया हुआ है। लेकिन बाबरी मस्जिद' मुद्दे में मुसलमानों को खुश करने की जो अपील है, वह दूसरे मुद्दों में नहीं है।

निजी कंपनियों से बिजली खरीदी के मायने

नजरिया
राज कुमार सिन्हा
लेखक 'बरगी बांध विस्थापित संघ' के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं।

'मध्यप्रदेश विद्युत मंडल' के पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तावित बिजली खरीदी पर 'विद्युत नियामक आयोग' के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष कोयले पर सरचार्ज की समाप्ति, 'जीएसटी' दर में कमी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा थर्मल पावर प्लांट में लगने वाले 'फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन' (एफजीडी प्रणाली में उत्सर्जन से सल्फर यौगिकों को हटाया जाता है) तकनीक की अनिवार्यता के खत्म होने को बिजली खरीदी समझौते में शामिल नहीं किया गया है। अग्रवाल ने आयोग से मांग की है कि बिजली खरीदी प्रस्ताव व संबंधित पूंजीगत लागत की गहन समीक्षा के बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी दें।

मध्यप्रदेश सरकार भविष्य की जरूरतों के लिए निजी कंपनियों से 25 वर्षों के लिए, चार हजार मेगावाट बिजली, 5.83 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी समझौता करने की तैयारी कर रही है। इसकी अंतिम मंजूरी के लिए 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग' को प्रस्ताव भेजा गया है। जानकार बताते हैं कि यदि प्रस्तावित दर को मंजूरी मिली तो प्रदेश को 25 साल में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना होगा, जिसका भार उपभोक्ताओं पर पडेगा।

'मध्यप्रदेश विद्युत मंडल' के पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तावित बिजली खरीदी पर 'विद्युत नियामक आयोग' के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष कोयले पर सरचार्ज की समाप्ति, 'जीएसटी' दर में कमी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा थर्मल पावर प्लांट में लगने वाले 'फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन' (एफजीडी प्रणाली में उत्सर्जन से सल्फर यौगिकों को हटाया जाता है) तकनीक की अनिवार्यता के खत्म होने को बिजली खरीदी समझौते में शामिल नहीं किया गया है। अग्रवाल ने आयोग से मांग की है कि बिजली खरीदी प्रस्ताव व संबंधित पूंजीगत लागत की गहन समीक्षा के बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी दें।

मध्यप्रदेश में बिजली की उपलब्धता और खरीदी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। प्रस्तावित बिजली खरीदी और निजी कंपनियों से हुए महंगे बिजली खरीदी समझौतों को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बिजली दरों में बढ़ोतरी और 'डिस्कॉम' (विद्युत वितरण कंपनी) पर बढ़ते वित्तीय दबाव ने राज्य में ऊर्जा प्रबंधन को नई बहस के केंद्र में ला दिया है। ऊंचे दामों पर की जा रही बिजली खरीदी से न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा है, बल्कि उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी प्रभावित हो रही है।

राज्य में पिछले कुछ वर्षों से बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी और बिलों में अनियमितताएं आम उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यवसायी के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। बिजली खरीद नीतियों, निजी कंपनियों से महंगे समझौतों और 'डिस्कॉम' की अक्षमताओं (लाइन लॉस, बिजली चोरी, प्रबंधन की कमियां और पुराना घाटा) का बोझ सीधे जनता पर पड़ रहा है। बिजली बिल में एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल कॉस्ट, ड्यूटी चार्ज जुड़ते हैं। बिजली की दरों में वृद्धि के अनुपात में ही बाकी सारे चार्ज बढ़ते-घटते हैं।

मध्यप्रदेश में निजी बिजली कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीदी का मुद्दा विभिन्न 'कैग' (सीएजी) रिपोर्टों, अध्ययनों और सार्वजनिक बहसों में उठता रहा है। यह पुराने 'पावर पर्चेज एग्रीमेंट,' महंगे फिक्स्ड चार्ज और पारदर्शिता की कमी से अधिक जुड़ा हुआ है। राज्य में बिजली उत्पादन और खरीदी का काम तीन मुख्य स्तरों पर होता है। 'मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी' राज्य की 'डिस्कॉम' के लिए बिजली खरीदने की नोडल एजेंसी है। 'कैग' की रिपोर्टों में 'पावर मैनेजमेंट कंपनी' की नीतियों पर सवाल उठते रहे हैं, जैसे - महंगी दरों पर निजी कंपनियों से बिजली खरीदी अनुबंध किया जाना आदि।

कुछ निजी कंपनियों से बाजार भाव से अधिक में बिजली खरीदी गई। वहां खरीदी अनुबंध के 'फिक्स्ड चार्ज' के कारण बिजली महंगी पड़ी। 'टेक ऑर पे' प्रावधान के कारण कई निजी कंपनियों के साथ ऐसे समझौते हैं कि बिजली लो या मत लो, फिर भी भुगतान करना पड़ता है। एक जानकारी के अनुसार सन् 2020 से 2022 के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने निजी बिजली कंपनियों को 1,773 करोड़ रूपए का भुगतान किया, जबकि उनसे एक यूनिट बिजली नहीं खरीदी गई। यह लागत उपभोक्ताओं के बिलों में जुड़ती रही।

कुछ बिजली खरीदी अनुबंधों में ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे निजी कंपनियों ने ईंधन की बढी हुई लागत भी राज्य पर डाल दी। मैनेजमेंट कंपनी ने इस महंगे कोयले या ईंधन का पैसा उपभोक्ताओं से वसूला। 'कैप्टिव प्राइवेट प्लांटों' से मध्यप्रदेश ने 4.50 से 6 रूपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदी, जबकि बाजार में यह दर 2 से 3 रूपए प्रति यूनिट थी।

सरकारी कंपनियों की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद निजी कंपनियों से बड़ी मात्रा में बिजली खरीदने पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। ऊर्जा अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह बिजली खरीदी समझौता 2010 से 2015 के दौरान हुआ था, जब कोयले की कीमतें अधिक थीं। आज बाजार सस्ता हो गया है, लेकिन पुराने अनुबंधों ने मध्यप्रदेश को महंगी बिजली खरीदने के लिए बाध्य किया है। नियामक आयोग की निगरानी पर्याप्त मजबूत नहीं है। मूल्य निर्धारण और खरीद में अधिक पारदर्शिता होना चाहिए।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 200 यूनिट मासिक खपत पर मध्यप्रदेश में बिल करीब 1,425 रूपए है, जबकि छत्तीसगढ़ में 900 रूपए और गुजरात में 785 रूपए है। वहीं 300 यूनिट खपत पर मध्यप्रदेश में 2,342 रूपए, जबकि छत्तीसगढ़ में 1,450 और गुजरात में 1,253 रूपए बताया गया है। प्रति यूनिट दरों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी जा रही है। कई घरों में औसत घरेलू बिल 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़े हैं। बिजली बिल घर के मासिक खर्च का बड़ा हिस्सा खा जाता है जिससे रसोई बजट में कटौती हो रही है। ईएमआई, स्कूल फीस, किराया और रसोई खर्च पहले से ही महंगा है और बिजली बिल बढ़ने से मध्यम वर्ग की मासिक बचत लगभग खत्म हो गई है। कई परिवार अवकाश, यात्रा और अन्य खर्च रोक रहे हैं।

उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान किश्तों में कर रहे हैं। राहत की बात है कि सरकार ने 'समाधान योजना' 2025-26 में शुरू की है, जिसके तहत बकाया बिलों पर छूट और भुगतान के आसान विकल्प दिए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिल पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा आ रहे हैं। कई जिलों में बिजली बिलों के खिलाफ जन-सुनवाईयों में तीन गुना शिकायतें दर्ज हो रही हैं। उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि बिल में 'अतिरिक्त चार्ज' वास्तविक खपत से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल सुधार और मीटर रीडिंग की समस्याएं लगातार आ रही हैं।

मध्यप्रदेश सरकार को महंगे निजी समझौतों को बदलकर दरें कम करने का प्रयास करना चाहिए। कई राज्यों में घरेलू उपभोक्ताओं पर फिक्स्ड चार्ज बेहद कम हैं। मध्यप्रदेश को भी ऐसा करना चाहिए। पुरानी कोयला आधारित यूनिटों को तकनीकी सुधार के साथ चलाना अधिक सस्ता विकल्प हो सकता है। सौर और पवन ऊर्जा स्रोतों से प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली उपलब्ध है, जिसे प्राथमिकता देने की जरूरत है। मध्यप्रदेश में बिजली की बढ़ती कीमतें सिर्फ 'महंगी बिजली' का मुद्दा नहीं है। यह घरेलू जीवन, किसान, उद्योग, रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित कर रहा है। उपभोक्ताओं की मांग है कि बिजली की दरें आम आदमी की पहुंच में हों।

'एशियन डेवलपमेंट बैंक' की सिफारिश पर गठित 'टाटाराव कमिटी' की सलाह पर 2003 में विद्युत मंडल के घाटे को खत्म करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली कम्पनियों का गठन किया था। वर्ष 2000 में विद्युत मंडल के समय घाटा 2100 करोड़ रुपए था, परन्तु मार्च 2024 तक, मध्यप्रदेश की 'बिजली वितरण कंपनियों' का कुल घाटा बढ़कर 69,301 करोड़ रुपए हो गया है। सुधार के नाम पर 'विद्युत अधिनियम 2003' लाया गया, जिसके नतीजे में उपभोक्ताओं को महंगी बिजली और निजी कंपनियों को भारी-भरकम मुनाफा मिल रहा है, जबकि 1948 का 'इलेक्ट्रिसिटी एक्ट' बिजली को सेवा क्षेत्र में रखकर सभी को उचित दर पर बिजली उपलब्ध कराता था। (सप्रेस)

भारत का उभरता वैश्विक कद

जी- 20 शिखर सम्मेलन
ममता कुशवाहा
लेखक शिक्षक हैं।

विश्व राजनीति के समकालीन परिदृश्य में हाल ही में जोहानसबर्ग में सम्पन्न हुआ जी- 20 शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज हो गया। अफ्रीकी धरती पर पहली बार आयोजित इस वैश्विक मंच ने उस परिवर्तनकारी युग की आहट दी, जिसमें दुनिया का शक्ति-संतुलन अधिक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय स्वरूप ग्रहण करने की ओर अग्रसर है। यह सम्मेलन केवल प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक बैठक भर नहीं रहा, बल्कि इसने उभरते वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए समानता, सहभागिता और समावेशी विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए। इन परिवर्तनों के केंद्र में भारत रहा, जो इस बार केवल एक सहभागी नहीं, बल्कि एक प्रेरक, संयोजक और दूरदर्शी नेतृत्व के रूप में उभरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भूमिका ने सम्मेलन की चर्चाओं को विकास सहयोग, जलवायु वित्त, तकनीकी परिवर्तन, कर्ज संकट और संस्थागत सुधार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रखा। पूरा सम्मेलन मानो इस विचार को दोहरा रहा था कि 'विकास एक साझा यात्रा है, किसी एक राष्ट्र की नहीं।'

जोहानसबर्ग सम्मेलन का सबसे अनोखा और प्रभावशाली पहलू था, विकासशील देशों की व्यापक और सशक्त भागीदारी। यह सम्मेलन अफ्रीका के राजनीतिक और आर्थिक महत्व को वैश्विक विमर्श के केंद्र में लाने वाला एक निर्णायक अवसर बना। दशकों से अफ्रीकी राष्ट्र यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें वैश्विक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिले तथा निवेश, व्यापार और तकनीक के क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किए जाएँ। जोहानसबर्ग में इन आवाज़ों को न केवल मंच मिला, बल्कि भारत जैसा दृढ़ समर्थक भी मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि विश्व के उत्तर और दक्षिण का विकास एक-दूसरे पर निर्भर है, और यदि दुनिया को स्थिरता चाहिए तो अफ्रीका की आकांक्षाओं का सम्मान अनिवार्य है। भारतीय नेतृत्व ने याद दिलाया कि अफ्रीकी संघ को जी- 20 की सदस्यता दिलाने का प्रस्ताव भारत ने ही रखा था, जिसे पिछले वर्ष मंजूरी मिली। यह पहल इतिहास में दर्ज हो चुकी है और भारत- अफ्रीका संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।

जोहानसबर्ग की चर्चाओं में जलवायु परिवर्तन सबसे प्रमुख मुद्दों में रहा। विश्व के विकासशील देशों ने जोर दिया कि वे जलवायु संकट के सबसे बड़े पीड़ित हैं, जबकि प्रदूषण में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत ने जलवायु न्याय का पुरजोर समर्थन किया, जिसका अर्थ है कि विकसित राष्ट्र अधिक जिम्मेदारी लें और विकासशील देशों को पर्याप्त वित्त, तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराएँ। भारत ने सतत जीवनशैली, सौर ऊर्जा, हरित विकास और परिपत्र अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर व्यवहारिक सुझाव दिए। इसके साथ ही भारत ने विकसित देशों से यह भी कहा कि जलवायु वित्त की प्रतिबद्धताएँ ज़मीन पर उतारी जानी चाहिए, केवल काग़ज़ पर नहीं।

सम्मेलन का एक और केंद्रीय विषय था, वैश्विक डिजिटल परिवर्तन। दुनिया डिजिटल हो रही है, लेकिन डिजिटल विभाजन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने इस संदर्भ में अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को सामने रखा- आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, आरोग्य सेतु, कोविन और अन्य सेवाओं के माध्यम से भारत ने दिखाया कि किस तरह तकनीक को जनकल्याण का उपकरण बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल भविष्य ऐसा होना चाहिए जो असमानताओं को कम करे, न कि बढ़ाए। दुनिया ने इस भारतीय दृष्टिकोण की सराहना की और कई देशों ने भारत के साथ डिजिटल सहयोग को मजबूत करने में रुचि दिखाई।

जोहानसबर्ग सम्मेलन ने व्यावहारिक चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया, जैसे खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, स्वास्थ्य अवसंरचना और स्थायी निवेश। भारत ने खाद्य संकट के दौरान विश्व को अनाज उपलब्ध कराने की अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला। ऊर्जा सुरक्षा पर भारत ने कहा कि ऊर्जा विकल्पों में विविधता अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता न बनी रहे। वैश्विक स्वास्थ्य के विषय में भारत ने वैक्सीन उपलब्धता और चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने पर जोर दिया। कोरोना महामारी के दौरान भारत की भूमिका दुनिया ने देखी थी, वैक्सीन मैत्री और आपातकालीन सहायता के रूप में।

आज की दुनिया व्यापार युद्धों, क्षेत्रीय संघर्षों, सामरिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक नेतृत्व के अभाव जैसे गंभीर तनावों से घिरी हुई है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था लगातार अस्थिर होती जा रही है। ऐसे दौर में जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन ने दुनिया को यह सशक्त संदेश दिया कि टकराव और शक्ति-प्रदर्शन समस्याओं का समाधान नहीं हैं; बल्कि सहयोग, संवाद और बहुध्रुवीयता ही आगे बढ़ने का वास्तविक मार्ग है। यह सम्मेलन संकेत देता है कि विश्व अब किसी एकध्रुवीय शक्ति-संरचना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि एक ऐसे संतुलित वैश्विक ढांचे की ओर बढ़ रहा है जहाँ कई राष्ट्र मिलकर निर्णय लें और सामूहिक रूप से स्थिरता का निर्माण करें।

इस उभरती बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था में भारत एक विश्वसनीय, संतुलनकारी और कूटनीतिक रूप से सक्षम राष्ट्र के रूप में सामने आया है। उसकी विदेश नीति परस्पर सम्मान, संवाद और रचनात्मक सहयोग पर आधारित है, जो आज के विभाजित वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। भारत ने विभिन्न देशों के बीच सेतु का कार्य करते हुए मतभेदों को संतुलित किया और साझा समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है संयुक्त घोषणा-पत्र का सर्वसम्मति से पारित होना, जो आज के ध्रुवीकृत माहौल में लगभग असंभव उपलब्धि थी। यह न केवल भारत की कूटनीतिक प्रभावशीलता को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विश्व समुदाय भारत को एक स्थिर, विश्वसनीय और दूरदर्शी वैश्विक नेतृत्व के रूप में देख रहा है।

आज जब वैश्विक व्यापार तनाव, आपूर्ति-शृंखला टूटन, भू-राजनीतिक अविश्वास और आर्थिक अस्थिरता विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, तब यह साझा यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने इस संदर्भ में न केवल स्थायी और विश्वसनीय आपूर्ति-शृंखलाओं के निर्माण पर ज़ोर दिया, बल्कि यह भी बताया कि विकास तब तक समतामूलक नहीं हो सकता जब तक वैश्विक संस्थाएँ, जैसे संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और विश्व बैंक 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप खुद को न ढालें। 'वैश्विक प्रगति की साझा यात्रा' केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि आज की विश्व-व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकता है। यह वही मार्ग है जो देशों को परस्पर निर्भरता को समझने, एक-दूसरे की चुनौतियों को स्वीकारने और सामूहिक समाधान ढूँढने की प्रेरणा देता है। भारत ने इस यात्रा की दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विश्व को याद दिलाया है कि भविष्य उन्हीं का होगा जो सबको साथ लेकर चलेंगे।

जोहानसबर्ग में सम्पन्न जी-20 शिखर सम्मेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि दुनिया तेजी से बदल रही है, एकाधिकार की नहीं, साझेदारी की ओर। भारत इस परिवर्तन के केंद्र में है- विश्वसनीय, संतुलित और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ। सम्मेलन के परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि भारत अब केवल वैश्विक चर्चाओं में भाग नहीं लेता, बल्कि उन्हें दिशा भी प्रदान करता है। एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और संतुलित विश्व-व्यवस्था का निर्माण अब कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक प्रक्रिया है और भारत इसका अग्रदूत बनकर उभर रहा है।

रूद्र सागर में जलकुम्भी पनपती ही क्यों है ?

उज्जैन पर्यावरण
संदीप कुलश्रेष्ठ

देशभर से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। किन्तु वे महाकाल मंदिर के निकट पौराणिक रूद्र सागर में पानी की जगह जलकुम्भी देखकर दुखी होकर आश्चर्य भी व्यक्त करते हैं। वर्तमान में रूद्र सागर में पानी की जगह जलकुम्भी ही जलकुम्भी दिखाई देती है। उसके लिए जिम्मेदार नगर निगम आँख मूंदे बैठा है।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम के पास आज नहीं बरसो से रूद्र सागर से जलकुम्भी हटाने के लिए जरूरी सभी संसाधन मौजूद हैं। किन्तु वे धूल खा रहे हैं। नगर निगम के पास कर्मचारियों की भी भरमार है। इसके बावजूद पौराणिक और ऐतिहासिक सप्तसागरों में से एक रूद्र सागर में पानी की जगह जलकुम्भी ही जलकुम्भी देखकर श्रद्धालुओं का मन दुख से भर आता है। नगर निगम के वरिश्ठ अधिकारी और संबंधित कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। इसी कारण जलकुम्भी पनपकर पूरे सागर पर छा जाती है।

पौराणिक रूद्रसागर में पानी की जगह जलकुम्भी को देखकर जब मीडिया में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित हुए तो कलेक्टर श्री रोशनकुमार सिंह ने रूद्र सागर का निरीक्षण किया और संबंधित को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब देखना यह है कि नगर निगम कब नींद से जागता है ? कलेक्टर को इसी प्रकार समय-समय पर रूद्र सागर का निरीक्षण करते रहना चाहिए। उन्हें मीडिया में समाचार आने का इंतजार नहीं करना चाहिए।

पौराणिक रूद्रसागर में जल कुम्भी हो ही नहीं, इसके लिए एक स्थायी योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक स्थाई अमला तैनात करना जरूरी है। उस अमले को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वह अमला प्रतिदिन रूद्र सागर का नांव से निरीक्षण करे और जहाँ भी, जब भी जलकुम्भी पनपती दिखे, उसे तुरन्त हटा दें, तभी रूद्र सागर जलकुम्भी से मुक्त हो सकेगा।

उज्जैन के प्रसिद्ध सप्तसागर न केवल पौराणिक और ऐतिहासिक है, बल्कि जन-जन की धार्मिक आस्था से भी जुड़े हैं। इसे स्वच्छ और शुद्ध रखना हम

सबकी जिम्मेदारी है। रूद्र सागर ही नहीं सभी सप्त सागर हमारी धरोहर है। इसके संरक्षण की भी आवश्यकता है। अक्सर यह देखने में आता है कि सप्त सागरों में से किसी न किसी सागरों पर अतिक्रमण हो जाता है। अतिक्रमण हो जाने के बाद उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जरूरी यह भी है कि सप्तसागरों का सीमांकन हो और वहां बाउंड्री वॉल बना दी जाए, ताकि अतिक्रमण होने ही नहीं पाए। आमजन को भी चाहिए कि वे सप्तसागरों को स्वच्छ रखने में अपनी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

रुपया लुढ़कने की कथा

व्यंग्य
डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त
लेखक व्यंग्यकार हैं।

धर्मनिष्ठ नगर में मास्टर गंगाप्रसाद रहते थे, जो सुबह अख़बार पढ़कर देशभक्ति से भर जाते और शाम तक सब्ज़ी मंडी में प्याज़ की क़ीमत देख कर देश के आर्थिक भविष्य पर शोकसभा कर लेते।एक दिन उन्होंने जेब से पुराना चमकदार रुपया निकाला और बोले, 'देखो, ये वही रुपया है जो आज़ादी के बाद गोल बनाकर छोड़ा गया था, ताकि अर्थव्यवस्था 'गोल-मोल' तरीके से चले।' जैसे ही उन्होंने रुपया मेज़ पर रखा, वह लुढ़कते-लुढ़कते सीधे टीवी पर चल रहे चुनावी माननीय विकास नारायण, हर भाषण में कहते, 'रुपया हमारे संस्कारों की तरह मज़बूत है, बस थोड़ा विदेश घूमने निकला है।' वोटर इस वाक्य का अर्थ नहीं समझते, लेकिन ताली बजाते, क्योंकि ताली की आवाज़ में गैस सिलिंडर की कीमत दब जाती। नेता-जी की पार्टी ने घोषणा की कि अब डिजिटल भारत में नक़दी की ज़रूरत नहीं, इसलिए रुपये का गिरना कोई मुद्दा नहीं, बल्कि 'टेक्नोलॉजिकल प्रगति' है।

मास्टर गंगाप्रसाद ने ठान लिया कि गोल रुपये की यह त्रासदी अब नहीं चलेगी। उन्होंने नगर में 'चौरस रुपया मोर्चा' बना दिया और पोस्टर लगवाए - 'रुपया चौरस होगा, तो लुढ़केगा नहीं, सीधे जनता की जेब में बैठेगा।' कुछदिनों में मोर्चा इतना सफल हो गया कि बगल की चाय की दुकान पर भी पोस्टर चिपक गए: 'यहाँ चाय गोल, पर रुपया चौरस चाहिए।'

राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल ने इस पर बहस रखी - 'क्या चौरस रुपया राष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ है?' एक पक्ष के विशेषज्ञ बोले, 'गोल रुपया प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, चौरस रुपया विदेशी साज़िश।' दूसरे पक्ष ने जवाब दिया, 'जब अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, तो रुपया चौरस क्यों नहीं?' एंकर ने निष्कर्ष दिया, 'दोनों पक्ष मज़बूत हैं, असली सवाल यह है कि ब्रेक के बाद कौन-सा स्पॉन्सर आएगा।'

धर्मनिष्ठ नगर के प्रसिद्ध पंडित आत्मानंद शास्त्री ने घोषणा की कि रुपया गिरने का असली कारण ग्रह-दोष है, न कि सरकार-दोष। उन्होंने 'रुपया स्थिरीकरण यज्ञ' रखा, जिसमें शर्त थी कि हर भक्त कम से कम सौ रुपये की आहुति दे, ताकि रुपया 'आग में चढ़कर पवित्र होकर वापस आए।' भक्तों ने नोट चढ़ाए, पंडित जी ने थाली में चढ़ाया और बोले, 'यज्ञ सफल, अब रुपया और नहीं गिरेगा, बस जनता की जेब से गायब रहेगा।'

उधर नगर के उद्योगपति चाणक्यप्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कम्पनी घाटे में है, इसलिए सरकार से विशेष पैकेज चाहिए, वरना हज़ारों कर्मचारियों की नौकरियाँ खतरे में पड़ जाएँगी।सरकार ने तुरन्त पैकेज दे दिया; अगले ही महीने कम्पनी ने नया विदेशी कारखाना खोलने की घोषणा कर दी, पर कर्मचारियों के लिए बयान जारी हुआ - 'आपकी त्याग भावना से ही देश आगे बढ़ रहा है, आप घर बैठकर भी राष्ट्रनिर्माण में योगदान दे रहे हैं।' बेरोज़गार युवा ने यह सुनकर मोबाइल में डेटा रिचार्ज किया, ताकि नौकरी के बदले देशभक्ति वाले वीडियो कम से कम फ्री में देख सके।

कुछ महीनों बाद अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि देश की आर्थिक स्थिति 'स्थिर' है, मतलब गिरना बंद नहीं हुआ, गिरने की आदत स्थिर हो गई है।सरकार ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता कर विज्ञापन निकाला - 'देखिए, वैश्विक संस्थाएँ भी मानती हैं कि हमारा रुपया रोज़ एक-सा गिरता है, इसमें भी एक अनुशासन है।' मास्टर गंगाप्रसाद ने यह पढ़कर अपने चौरस रुपया मोर्चे की मीटिंग बुलाई और बोले, 'भाइयो, रुपया चाहे गोल हो या चौरस, असली बात ये है कि ये हमारी जेब से निकल कर पोस्टर, विज्ञापन और यज्ञ में पहुँच जाता है ङ्क और हम सोचते रहते हैं कि 'देश आगे बढ़ रहा है' या हम पीछे लुढ़क रहे हैं।'

अंत में धर्मनिष्ठ नगर के बुद्धिजीवियों ने सामूहिक रूप से निष्कर्ष निकाला कि रुपये का आकार बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक नागरिक अपने दिमाग़ का आकार थोड़ा बड़ा नहीं करते।पर नागरिकों ने ठान रखा था कि दिमाग़ की एक्सरसाइज़ से अच्छा मोबाइल की बैटरी की एक्सरसाइज़ की जाए, इसलिए रूपये की तरह उनका विवेक भी गोल-गोल घूमते-घूमते सीधे शून्य पर आ टिका। इस तरह नहरू जी का गोल रुपया, नेता जी के गोल-मोल भाषण और जनता के गोल-मटोल तर्क सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्रीय चक्रव्यूह में बदल गए, जिसमें घुसना आसान, निकलना असंभव- और हर तरफ सिर्फ़ यही आवाज़ गूँजती रही, 'रुपया गिर रहा है, पर चिंता मत कीजिए, टीवी पर सब कुछ 'नॉर्मल' दिख रहा है।'

विज्ञान और दण्डक्रम

गिरीश जोशी

संस्कृति अध्येता एवं लेखक

दण्डक्रम परायण का आधुनिक विज्ञान के नजरिए से विश्लेषण

पूज्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी अपनी पुस्तक साइंस ऑफ रिलीजन में लिखते है 'सृष्टि का मूल कंपन (Vibration) है' और जब यह कंपन सुना जाता है तो इसे नाद कहा जाता है। सृष्टि रचना में सर्वप्रथम ईश्वर द्वारा सूक्ष्म कम्पन-इच्छा (स्पंदन) उत्पन्न होती है। इससे आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द है।

ब्रह्मांड में सभी तत्वों के अपने-अपने स्पन्दन (vibratory patterns) हैं। सूर्य, तारे, ग्रह, पंच महाभूत, मानव शरीर एवं चक्र सब विशिष्ट आवृत्तियों पर स्पंदित हैं। ऋषि इन स्पन्दनों को 'श्रुति' रूप में सुनते थे। वे ध्यान से मिली समाधि अवस्था में ब्रह्मांडीय कम्पन को आध्यात्मिक कान (divine inner hearing) से सुनते थे। यही सुने गए मंत्र 'श्रुति' तथा आगे वेद मंत्र कहलाए। वेद मंत्र विशिष्ट ध्वनि, विशिष्ट आवृत्ति, विशिष्ट स्पन्दन का कुल योग है। स्वामीजी के अनुसार वेद मंत्र ब्रह्मांडीय स्पन्दनों की ध्वन्यात्मक संरचना हैं। आगे वे कहते है वेद-मंत्र ब्रह्मांडीय कंपन का 'मानवीय शब्द-रूप' है।

महर्षि महेश योगी के अनुसार वेद मंत्र पूर्णतः वैज्ञानिक और प्राकृतिक नियमों (Laws of Nature) का शुद्ध स्वरूप है । वे कहते हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का नियम है, वैसे ही वेद के मंत्र भी प्रकृति की आंतरिक संरचना का वर्णन हैं।

वेद प्रकृति की परिपूर्ण कार्यप्रणाली का सूक्ष्म गणित है। वे वेद मंत्रों को science of natural law कहते थे। वे अक्सर कहते थे कि वेद प्रकृति के नियमों का पूर्ण कोड (complete code) है।

वेद मंत्रों का प्रभाव

प्रत्येक वेद मंत्र एक विशिष्ट कम्पन (vibration) उत्पन्न करता है। ये कम्पन मानव शरीर, मन और पूरे परिवेश पर प्रभाव डालते हैं। इन मंत्रों का सही मंत्र-उच्चारण, प्राण, मन, नाड़ी, चक्र को विशेष कम्पन-मिलन (resonance) में लाता है।

ब्रह्मांड की मूल आवृत्ति (Cosmic Frequency) है।

सभी वेद मंत्र इसी मूल-आवृत्ति से जुड़े उप-तरंग (sub-harmonics) हैं। मानव शरीर एक 'ब्रह्मांडीय रिसीवर' है। शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, 7 चक्र है।

सब ध्वनि-आधारित कंपन-संवेदी प्रणाली की तरह काम करते हैं। इसलिए मंत्र और नाद शरीर को नाड़ी-स्तर पर प्रभावित करते हैं । जैसे कोई ट्यूनिंग फोर्क एक विशेष आवृत्ति पर ट्यून हो जाता है।

वैदिक मंत्रों की मात्राएँ, स्वर, दीर्घ-ह्रस्व, विराम, लय, एक fi&ed vibratory pattern हैं । मंत्र का प्रभाव कंपन द्वारा होता है, शब्दार्थ से नहीं। वे कहते हैं कि 'मंत्र का फल अर्थ से नहीं, स्पन्दन से उत्पन्न होता है।' मंत्र ऊर्जा-केन्द्र (चक्र) को सक्रिय करते हैं

दण्ड पारायण

'दण्ड' का अर्थ है खंड , अनुच्छेद या स्टेप, किसी मंत्र, सूक्त, या स्तोत्र को निश्चित छोटे-छोटे खंडों (दण्डों) में विभाजित करके पढ़ने को दण्डक्रम कहा जाता है। मंत्र के हर शब्द/वाक्यांश को सम्पूर्ण स्वर-वर्ण, मात्रा, उच्चारण के साथ व्यवस्थित क्रम में पढ़ा जाता है। दण्डक्रम में एक मंत्र या श्लोक को कई विन्यासों/खंडों में पढ़ा जाता है। ध्वनि-तरंगें हर विन्यास में अलग पैटर्न बनाती हैं।

उदाहरण के लिए

मंत्र A B C D E F है, तो दण्डक्रम में इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगाः दण्ड 1: A, दण्ड 2: A B, दण्ड 3: B C, दण्ड 4: C D, दण्ड 5: D E , दण्ड 6: E F, दण्ड 7: F यानी हर पाठ में कंपन का आरम्भ, मध्य, और समाप्ति बदल जाती है, जिससे मंत्र के पूरा स्पंदन-क्षेत्र (vibration field) सक्रिय होता है। यह वैदिक ध्वनि-विज्ञान का अत्यंत वैज्ञानिक पक्ष है।प्राचीन वैदिक ध्वनि-विज्ञान को आधुनिक विज्ञान की शब्दावली जैसे एकोस्टिक्स, न्यूरोसाइंस, और रिज़ोनेंस (अनुनाद) के सिद्धांतों से जोड़कर समझा जा सकता है। दण्डक्रम संरचित (Structured) ध्वनि-कंपन तकनीक है।

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नाद का अर्थ सिर्फ 'सुनाई देने वाली ध्वनि' नहीं है होती है। वह तो sound, energy, vibration, resonance का संयुक्त रूप है।

आधुनिक विज्ञान की परिभाषिक शब्दावली के अनुसार नाद यानी निर्दिष्ट आवृत्ति (frequency),स्वर अर्थात् ध्वनि का आयाम (amplitude), उच्चारण का मतलब तरंग आकृति (waveform) और मात्रा का अर्थ समय-लय (time domain) है। दण्डक्रम में इन सबका संयोजन अत्यंत सटीक रूप से किया जाता है।

पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मूलाधार से सहस्त्रार तक सात चक्रों में कुंडलनी शक्ति का प्रवास निर्बाध तरीके से हो इसके लिए इन चक्रों का शुद्धिकरण आवश्यक होता है। चक्रों के शुद्धिकरण के लिए अनेक प्रविधियों की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। उसी का एक प्रकार दण्डक्रम है। इसमें वेद मंत्रों के स्वरों की पुनरावृत्ति से आज्ञा चक्र कंपन-दृष्टि (inner clarity), अनाहत-भाव और करुणा का विस्तार, विशुद्धि-

वाणी/ध्वनि का शुद्धिकरण,मूलाधार- स्थिरता, मणिपुर से ऊर्जा संतुलित होते हैं।

दण्डक्रम पारायण का उद्देश्य

मंत्र के कंपन और स्वर-शुद्धि को स्थापित करना है। दण्डक्रम से स्वर, उच्चारण, मात्रा, नाद, अनुप्रास सब पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। मंत्र-शुद्धि, मन-प्राण की स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति, ध्वनि-ऊर्जा का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।

एकाग्रता में वृद्धि

दण्डक्रम में एकाग्रता बहुत अधिक लगती है। इससे मन स्थिर होता है, प्राण (life-force) संतुलित होता है,चेतना परिष्कृत होती है।

स्मरण-शक्ति का परिष्कार होता है क्योंकि एक ही मंत्र को अलग-अलग विन्यासों में पढ़ना होता है, इससे स्मरण-शक्ति (memory) बढ़ती है, भाषिक परिशुद्धि आती है,पाठक की क्षमता बढ़ जाती है। यह प्राचीन गुरुकुलों में अनिवार्य विद्या थी।

दंडक्रम के प्रकार

दण्डक्रम पारायण कई स्थानों पर किया जाता है जैसे रुद्रम दण्डक्रम (शिवोपासना में),चमक दण्डक्रम, वेदिक सूक्त दण्डक्रम,श्रीसूक्त दण्डक्रम, नारायणसूक्त दण्डक्रम महानारायणोपनिषद् पारायण आदि।

दण्डक्रम वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि इसमें मंत्र की हर ध्वनि को 'रोटेशनल कम्पन' मिलता है। पहली बार मंत्र शुरुआत से कंपन भेजता है,फिर मध्य से,फिर अंत से, फिर आधार से ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर ,फिर ऊर्ध्व से आधारगामी यानी नीचे। इससे एक ही मंत्र की वाइब्रेशन की ऊर्जा अनेक कोणों से शरीर में प्रवेश करती है।इसे भारतीय नाद-विज्ञान में 'बहुदिशात्मक कंपन (multi-directional resonance)' कहते हैं।

दण्डक्रम, नाड़ियों में 'Standing Waves' उत्पन्न करता है। ध्वनि के बार-बार दोहराव से शरीर की नाड़ियों और चक्रों में Standing Wave Patterns (स्थिर तरंगें), Constructive Interference (ध्वनियों का सहयोग), Resonance Peaks (उच्चतम अनुनाद) बनते हैं। इससे नाड़ियाँ खुलती हैं, प्राण का प्रवाह संतुलित होता है, चित्त स्थिर होता है।

दण्डक्रम की संरचना ऐसी है कि मस्तिष्क की तरंगें (brain waves) मंत्र के पैटर्न के साथ सिंक्रोनाइज़ होने लगती हैं। पहले बीटा अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा थीटा,गहरे अभ्यास में थीटा गामा में परिवर्तन होता है। यह वही अवस्था है जो ध्यान के उच्च स्तर एवं समाधि की दहलीज मानी जाती है।

ईश्वर का प्रथम 'स्पन्दन'

परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि जब निराकार ईश्वर इच्छा करता है कि 'मैं अनेक बनूँ' ('एकोऽहं बहुस्याम') तभी उसमें एक सूक्ष्म आत्मिक कंपित स्पन्दन उत्पन्न होता है। यह स्पन्दन ही प्रकृति (Cosmic Nature), प्राण (Cosmic Energy), सृष्टि के तत्त्व का मूल बनता है। समस्त ब्रह्मांड इसी स्पन्दन से बना है।

वे कहते हैं कि परमाणुओं का नृत्य, तारों का जन्म, मन की गति, कर्म का प्रवाह, सब उसी एक कॉस्मिक स्पन्दन के विविध रूप हैं।

स्पन्दन का अंत ईश्वरानुभूति

जब साधक अपने मन, प्राण, इन्द्रियों को योग के द्वारा स्थिर कर लेता है, तो वह स्पन्दन के क्षय का अनुभव करता है। स्पन्दन मिटते ही साधक, निराकार, चिदानन्द ब्रह्म को अनुभव करता है जिसे योगानंद जी "God beyond creation vibration" कहते हैं।

योगानंद जी के अनुसार 'जहाँ नाद है वहाँ ईश्वर-शक्ति है और जहाँ स्पन्दन का अंत है वहाँ ईश्वर स्वयं है।' इसलिए दण्डक्रम पारायण भी वेद मंत्रों को विशिष्ट क्रम में पढ़ने,अपने सप्त चक्र को शुद्ध करने, ईश्वर को जानने और उसी के साथ एकाकार होने की अब तक खोजी गई पद्धतियों में से एक महत्त्वपूर्ण पद्धति है। जिसे देवव्रत महेश रेखे ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपनी कड़ी लगन और कठिन परिश्रम से 200 वर्षों के बाद पुनः इस विश्व को स्मरण करवाया है।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर विशेष

डॉ.राघवेंद्र सिंह

लेखक पत्रकार हैं।

भ्रष्टाचार मुक्त भारतः स्वयं से सुधार का संकल्प

भ्रष्टाचार किसी भी राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा और समाज की जड़ों को खोखला करने वाली एक लाइलाज बीमारी के समान है। हर साल 9 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि सामूहिक नागरिक चेतना से ही संभव है। इस वर्ष का यह दिवस न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का प्रतीक है, बल्कि भारत के संदर्भ में यह आत्म-मंथन का भी समय है कि हमने इस 'सामाजिक बुराई' से निपटने में कितनी दूरी तय की है और अभी कितनी राह बाकी है। भारतीय राजनीति और प्रशासन के इतिहास में एक दौर वह भी था, जब भ्रष्टाचार को व्यवस्था का हिस्सा मान लिया गया था।

देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार जब दिल्ली से 1 रुपया भेजती है, तो गरीब की जेब तक केवल 15 पैसे ही पहुँचते हैं। वह 85 पैसों का 'लीकेज' बिचौलियों, भ्रष्ट अधिकारियों और पारदर्शी तंत्र के अभाव की भेंट चढ़ जाता था। यह केवल आर्थिक हानि नहीं थी, बल्कि करोड़ों देशवासियों के भरोसे की हत्या थी। संसाधनों का यह असमान वितरण और संस्थागत भ्रष्टाचार ही वह कारण था, जिसने दशकों तक भारत के विकास की गति को थामे रखा। वर्तमान परिदृश्य में, विशेषकर पिछले दशक में, भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध तकनीकी प्रहार किया है। मोदी सरकार की वर्तमान कार्य प्रणाली और 'डिजिटल इंडिया' अभियान ने शासन में अभूतपूर्व पारदर्शिता का संचार किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की नीति ने उन बिचौलियों को व्यवस्था से बाहर कर दिया है जो गरीबों का हक मारते थे। आज जब केंद्र से पैसा चलता है, तो वह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में बिना किसी कटौती के पहुँचता है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कुछ प्रमुख कारकों ने बड़ी भूमिका निभाई है। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण होने से मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है, जिससे 'सुविधा शुल्क' या रिश्वत की गुंजाइश घटी है। जीएसटी जैसी एकीकृत कर प्रणाली ने कर चोरी को कठिन बना दिया है और व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाई है। बेनामी संपत्ति अधिनियम और भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून जैसे कदमों ने भ्रष्टाचारियों के मन में कानून का भय पैदा किया है।भ्रष्टाचार केवल फाइलों या दफ्तरों तक सीमित नहीं है।

यह एक

मानसिक प्रवृत्ति भी है। अक्सर हम तंत्र को दोष देते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए शॉर्टकट खोजने से

नहीं चूकते। यहाँ यह नारा अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है–'सुधार की शुरुआत स्वयं से करनी होगी।' यदि समाज भ्रष्टाचार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना शुरू कर दे और नागरिक 'लेने' और 'देने' दोनों से इनकार कर दें, तो कोई भी भ्रष्ट तंत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। 'हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा' का मंत्र हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी एक व्यक्तिगत विकल्प है जो आगे चलकर एक सामाजिक क्रांति का रूप ले लेती है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में सत्यनिष्ठा अपनाता है, तो भ्रष्टाचार की जड़ें अपने आप कमजोर होने लगती हैं। कानून और तकनीक भ्रष्टाचार को कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसे जड़ से मिटाने के लिए सामाजिक चेतना और जागरूकता अनिवार्य है। जब तक समाज में भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक इस बुराई का पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं है। आगामी समय में हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षाः स्कूलों और परिवारों में ईमानदारी को सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्थापित करना।

व्हिसलब्लोअर का संरक्षणः उन साहसी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं।

प्रशासनिक जवाबदेहीः लोक सेवकों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना ताकि वे स्वयं को 'स्वामी' नहीं बल्कि 'सेवक' समझें। निष्कर्ष यह कि 9 दिसंबर का यह दिन केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा का दिन है। भारत आज विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इस गौरवशाली यात्रा में भ्रष्टाचार की बेड़ियाँ हमारे पैरों में नहीं पड़नी चाहिए। सरकार ने नीतिगत स्तर पर पारदर्शिता का जो ढांचा तैयार किया है, उसे सशक्त बनाने की जिम्मेदारी अब समाज की है।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब 140 करोड़ भारतीय यह ठान लेंगे कि वे न तो भ्रष्टाचार का हिस्सा बनेंगे और न ही इसे मूकदर्शक बनकर सहेंगे। आइए, इस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर हम स्वयं से सुधार का संकल्प लें, क्योंकि पारदर्शी भारत ही समृद्ध भारत की नींव है।

शिक्षा व्यवस्था

रमाकान्त प्रसाद

लेखक केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य रहे हैं।

कितना आसान है मैकाले पद्धति से मुक्ति पाना?

मैकाले की शिक्षा व्यवस्था भारत में 1835 से लागू होती चली आ रही है। 2035 तक इस व्यवस्था को दो सौ वर्ष पूरे हो जाएंगे। इतनी लंबी अवधि में कोई भी प्रणाली केवल संस्था या नियम नहीं रहती; वह लोगों के मन, उनके व्यवहार, उनकी आकांक्षाओं और समाज की संरचना का हिस्सा बन जाती है। यह उसी तरह है जैसे मानव शरीर की 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएँ मिलकर एक जीवित, सजग और अत्यंत जटिल इकाई बनाती हैं। सामाजिक ढांचा भी वैसा ही है असंख्य मनुष्य अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं और अनुभवों के साथ मिलकर एक समाज को आकार देते हैं। शिक्षा इस समाज का केंद्रीय तत्व होती है, जो पीढ़ियों के बीच अनुभवों को ले जाती है, व्यक्तित्व को गढ़ती है, और एक राष्ट्र के सामूहिक जीवन को दिशा देती है।

अयोध्या में हाल ही में दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही कि भारत को वर्ष 2035 तक 'गुलामी की मानसिकता' से पूरी तरह मुक्त होना ही होगा। उनका संकेत विशेष रूप से मैकाले की शिक्षा व्यवस्था की ओर था, जिसे उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता का सबसे मजबूत स्तंभ बताया। इस घोषणा ने एक पुराना प्रश्न फिर से हमारे सामने रख दिया क्या वास्तव में मैकाले की शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह छुटकारा पाना आसान है? दो सौ वर्षों से जमी किसी संरचना को मिटाना क्या केवल नए पाठ्यक्रम, नई नीतियों या नए नारे से संभव हो सकता है?

मैकाले की शिक्षा व्यवस्था भारत में 1835 से लागू होती चली आ रही है। 2035 तक इस व्यवस्था को दो सौ वर्ष पूरे हो जाएंगे। इतनी लंबी अवधि में कोई भी प्रणाली केवल संस्था या नियम नहीं रहती; वह लोगों के मन, उनके व्यवहार, उनकी आकांक्षाओं और समाज की संरचना का हिस्सा बन जाती है। यह उसी तरह है जैसे मानव शरीर की 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएँ मिलकर एक जीवित, सजग और अत्यंत जटिल इकाई बनाती हैं। सामाजिक ढांचा भी वैसा ही है असंख्य मनुष्य अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं और अनुभवों के साथ मिलकर एक समाज को आकार देते हैं। शिक्षा इस समाज का केंद्रीय तत्व होती है, जो पीढ़ियों के बीच अनुभवों को ले जाती है, व्यक्तित्व को गढ़ती है, और एक राष्ट्र के सामूहिक जीवन को दिशा देती है।

यदि शिक्षा किसी समाज की आत्मा है, तो यह भी समझना आवश्यक है कि समय के साथ इस आत्मा पर क्या-क्या परतें चढ़ती गईं। शिक्षा का मूल उद्देश्य समग्र विकास, नैतिकता, रचनात्मकता, समान अवसर और सांस्कृतिक पहचान होना चाहिए था। लेकिन मैकाले की व्यवस्था आने से पहले और उसके बाद, इन उद्देश्यों को कई बार नजरअंदाज़ किया गया। शिक्षा नौकरी-केंद्रित बनने लगी, चरित्र निर्माण हाशिये पर चला गया, रचनात्मकता की जगह रटने और परीक्षा संस्कृति ने ले ली, समानता के सिद्धांत को जाति, लिंग और आर्थिक विषमताओं ने कमजोर कर दिया, और भाषा व संस्कृति को अंग्रेज़ी-प्रधान सोच ने धीरे-धीरे धुंधला कर दिया। आश्चर्य नहीं कि इन प्रभावों की छाया आज भी हमारे स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक व्यवहार में साफ दिखाई देती है।

यदि हम थोड़ा और पीछे लौटें, तो पता चलता है कि उपनिवेशिक प्रभाव सिर्फ मैकाले के मिनट्स से नहीं आया था। प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा और सामाजिक संरचना कर्म और गुण पर आधारित थी, पर बाद के कालखंड में यह व्यवस्था कठोर हो गई। ब्रिटिश शासन के उभार के समय तक समाज में पेशों का वंशानुगत होना शुरू हो चुका था, जिससे अंग्रेजों के लिए सामाजिक नियंत्रण आसान हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद मिशनरियों द्वारा खोले गए स्कूलों और 1813 के चार्टर एक्ट ने शिक्षा के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। अब शिक्षा केवल ज्ञान नहीं रही, बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव का एक माध्यम बन गई, जिसके द्वारा आधुनिक विषयों के साथ-साथ पश्चिमी विचारधारा भी धीरे-धीरे भारतीय

समाज में प्रविष्ट होने लगी।

समाज आधारित शिक्षा जब शासन आधारित शिक्षा में बदल गई, तो शिक्षक की भूमिका भी बदल गई। जहाँ पहले गुरु समाज के मार्गदर्शक और आदर्श होते थे, वहीं अब वे पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली के भीतर बंधे हुए कर्मचारी बन गए। सोच और दृष्टिकोण रचनात्मकता से हटकर अंकों और परिणामों पर आ गए, स्वतंत्रता कम होती गई और शिक्षक की सामाजिक प्रतिष्ठा भी धीरे-धीरे घटती चली गई। इस पूरे बदलाव ने शिक्षा को एक जीवंत और स्वायत्त प्रक्रिया से निकालकर एक प्रशासनिक ढांचे की मशीनरी में बदल दिया।

ऐसी परिस्थितियों में यह सोचना कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से पूरी मुक्ति पाना आसान है, अपने आप में एक सवाल है। यह केवल एक नीति या किताब नहीं, बल्कि एक मानसिकता है–जो भाषा, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और ज्ञान की परिभाषा तक में दिखाई देती है। लगभग दो शताब्दियों से जमी हुई इस संरचना को बदलना स्वाभाविक रूप से कठिन है। लेकिन यह असंभव भी नहीं है।

मुक्ति का पहला कदम मानसिक स्तर पर उठाया जाना चाहिए। भाषा और सोच में आत्मविश्वास लौटाना आवश्यक है। अंग्रेज़ी ज्ञान का माध्यम है, श्रेष्ठता का मानक नहीं। जब माता-पिता, शिक्षक और समाज यह समझने लगेंगे कि भारतीय भाषाएँ केवल बातचीत के साधन नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और विचार की मजबूत वाहक हैं, तब बदलाव की शुरुआत होगी।

दूसरा कदम पाठ्यक्रम और नीतियों में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुभाषी शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल-आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट और शोध-आधारित पद्धतियाँ–इन सबके माध्यम से सही दिशा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन नीति तभी सफल होती है जब वह शिक्षण-कक्षाओं में वास्तविक अनुभव बन सके।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम सामाजिक और आर्थिक स्तर पर है। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल संसाधन, तकनीकी सामग्री, विज्ञान और उद्यमिता के प्रशिक्षण की उपलब्धता अनिवार्य है। नौकरी के बाजार में भाषा नहीं, बल्कि कौशल प्राथमिकता बने। शिक्षा नौकरी-उन्मुख न होकर जीवन-उन्मुख बने, जहाँ आनंद, अर्थ और आत्मविश्वास साथ-साथ बढ़ें।

अंततः, यह यात्रा कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। शिक्षा एक व्यक्ति की नहीं, समाज की सामूहिक चेतना का विषय है। यदि हम मिलकर इसे केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक हित के रूप में देखें–सहयोग करें, नई राहें बनाएं और अपनी जड़ों को पहचानते हुए भविष्य की ओर आगे बढ़ें–तो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से मुक्ति का लक्ष्य एक दिन अवश्य पूरा होगा।

यह मुक्त होना केवल एक प्रणाली से दूर जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई उस भारतीय आत्मा को पुनः पहचानना और स्वीकार करना है, जो सहज, रचनात्मक, नैतिक और आनंदमय जीवन की आधारशिला रही है। यही वह मार्ग है जो हमें 2035 के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026, 6 से 10 दिसंबर तक

बीएलओ-बीएलए की बैठकों में अनुपस्थित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की अंतिम सूची की जाएगी तैयार

भोपाल (नप्र)। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के प्रथम चरण के अंतर्गत गणना पत्रकों के प्रकाशन एवं प्राप्ति के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान और सत्यापन के लिए जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर 6 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक बीएलओ-बीएलए तथा सहयोगी कार्मिकों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

इन बैठकों में ऐसे मतदाताओं की अंतिम सूची तैयार की जा रही है और उसे संबंधित मतदान केन्द्रों पर प्रदर्शित भी किया जा रहा है। जिन घरों से अब तक गणना पत्रक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी जानकारी भी बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

बैठक की कार्यवाही तथा संबंधित फोटोग्राफ को संबंधित जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे आम मतदाता आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए से अनुरोध किया गया है कि वे प्रदर्शित सूची का अवलोकन करें और यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो उसकी सूचना 11 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध कराएं ताकि बीएलओ ऐप के माध्यम से समय पर संशोधन किया जा सके। गणना पत्रक प्राप्त होने पर–अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को छोड़कर–अन्य सभी के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

बिना टैक्स जमा किए लोग मुफ्त में पी रहे नपा का पानी

अवैध नल कनेक्शन से नपा कर्मचारी परेशान, आर्थिक तंगी से जूझ रही नपा, अब रिकॉर्ड खंगालने में जुटी

बैतूल/आमला। लगभग 23 करोड़ सालाना बजट वाली नगर पालिका के पास जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कर्मचारियों के वेतन तक के लाले पड़ रहे हैं। इस माह जब कर्मचारियों को दो माह का वेतन मिलना था, तब नपा ने मात्र 15 दिन का वेतन दिया है, ऐसे में नगर पालिका की माली हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते कई वर्षों से लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रही नगर पालिका आमला को इन हालातो में पहुंचाने के लिए काफी हद तक शासन-प्रशासन की अदूरदर्शिता और लापरवाही को जिम्मेदार माना जा सकता है। बात चाहे विभिन्न करों की वसूली के हो या जलकर या अन्य किसी भी माध्यम से नपा के आय के स्रोत की बात करें, सभी मोर्चों पर कर्मचारियों की लापरवाही ने शहर की सरकार का बजट पूरी तरह चरमरा कर रख दिया है। नपा के अकाउंटेंट बाबूराव धोटे इस मामले को आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया बताते हुए कहते हैं कि नगरपालिका का सालाना बजट लगभग 23 करोड रुपए है, किंतु इस समय हमारे पास तमाम करों की वसूली का लगभग 70 लाख रुपए और चुंगी क्षतिपूर्ति के माध्यम से

लगभग 4 करोड रुपए ही नगरपालिका को मिल रहे हैं, ऐसे में नगर पालिका की खस्ता होती माली हालत का सहजता से ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

नल कनेक्शन का नहीं मिल रहा रिकॉर्ड- शहर के कईयों नल कनेक्शन उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। नपा के जल शाखा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार पूरे शहर के 18 वार्डों में 3 हज़ार नल जल उपभोक्ता ही है, किंतु बीते वर्षों में जलावर्धन कंपनी द्वारा लगभग इतने ही नए नल कनेक्शन शहर के उपभोक्ताओं को दिए हैं। कंपनी ने किन उपभोक्ताओं को नल कनेक्शन दिए हैं, उनका ना तो कोई रिकॉर्ड मिल रहा है और ना ही ऐसे उपभोक्ताओं से किसी तरह की कोई राशि वसूल की गई है। और ना ही ये जल कर जमा कर रहे। इस प्रकार बिना टैक्स जमा किए ही ये लोग मुफ्त में नपा का पानी उपयोग कर रहे हैं। अगर सूत्रों पर भरोसा करें तो पूरे शहर में 6612 नल कनेक्शनधारी है, किंतु नपा के रिकॉर्ड में केवल 3 हज़ार नल उपभोक्ता ही है। ऐसे में पेयजल आपूर्ति पर होने वाले अतिरिक्त खर्च भी नगरपालिका को ही वहन करना पड़ रहा है। और इसके बदले में नगरपालिका को उपभोक्ताओं से कोई राशि भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका की माली हालत और भी बिगड़ रही हैं।

दबाव बढ़ा, तो नोटिस का खेल हुआ शुरू

नगरपालिका उपभोक्ताओं से टैक्स वसूलने में फिसड्डी साबित होती रही है। नपा के कर्मचारी अब ऐसे नल कनेक्शन उपभोक्ताओं को ढूंढने का अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। जानकारी के अनुसार शहर में अब ऐसे लोगों को नोटिस भेज कर तलब किया जा रहा है, जो नपा के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाए हैं। यानि नपा खुद की गलतियों का ठीकरा अब उपभोक्ताओं पर फोडना चाहती है। इस मामले में नपा के टाइम कीपर गणेश हारोडे ने बताया है कि पूरे शहर में 6612 नल कनेक्शन है, लेकिन रिकार्ड में मात्र 3 हज़ार उपभोक्ता ही है, शेष उपभोक्ताओं को चिन्हित कर राशि वसूल की जाएगी। वहीं जलावर्धन कंपनी का भी ये दावा है कि नगरपालिका शुरू से ही कंपनी को कोई सहयोग नहीं कर रही है, जिससे आपसी तालमेल नहीं होने के कारण हालात बिगड़े हैं।

अब प्रदेश सरकार से सहयोग की उम्मीद

बीते कुछ वर्षों में जिस तरह नपा आमला की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती हैं, उससे पूरे शहर के विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। जानकार बताते हैं कि आमला नगरपालिका के इन हालातो में पहुंचने के कई कारण है, किंतु इस समय आमला नपा को बचाने के लिए प्रदेश सरकार सीधे दखल देकर ही नगरपालिका आमला को संकट से उभार सकती है।

इनका कहना है -

शहर में जलावर्धन कंपनी द्वारा बिना किसी वैधानिक नियम के लोगों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। शहर में जब नल कनेक्शन दिए जा रहे थे, तब नगरपालिका से किसी भी तरह की एनओसी और उपभोक्ताओं से कनेक्शन का चार्ज भी नहीं लिया गया। जिसके चलते कंपनी द्वारा दिए गए नल कनेक्शन का रिकॉर्ड नगरपालिका में दर्ज नहीं हो पाया है। हम कंपनी से इस बारे में बात कर रहे हैं।

- नितिन बिज़वे, सीएमओ, नगरपालिका आमला

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर

प्रदेश में दो लाख करोड़ के कार्यों का करेंगे भूमि-पूजन और लोकार्पण : सीएम यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुन्देलखंड में केन-बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुन्देलखंड में सिंचाई, उद्योग, पेयजल के लिए जो जल की कमी थी उसे पूरा किया जाएगा। नदी जोड़ो अभियान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई, उद्योग के लिए पर्याप्त जलराशि का प्रबंध किया जाएगा। नदी जोड़ो अभियान की प्रगति में मध्यप्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड समेत समूचे मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। छतरपुर में ओबेरॉय होटल का शुभारंभ इसी की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड में पर्यटन के साथ-साथ खनन एवं मेडिकल के क्षेत्र में विकास के लिये अनेक कार्य किये जा रहे है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार के माध्यम से बुन्देलखंड का विकास एवं उत्थान के लिये कार्ययोजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड कैसे आगे बढ़े इस पर लगातार सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड में उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास एवं उत्थान के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुन्देलखंड शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सागर में रानी अवंतिबाई महाविद्यालय का निर्माण, छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए धनराशि का आवंटन, पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों की स्थापना की गई है। इसी के साथ बुन्देलखंड अंचल में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से दक्ष प्रत्येक विद्यार्थी को रोजगार मिले, इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने के लिए अब अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हीं क्षेत्रों में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। खजुराहो में आयोजित कैबिनेट बैठक इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागीय समीक्षा में विगत दो वर्षों के कार्यों की समीक्षा और आने वाले तीन साल के लक्ष्य तय करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी माह की 21 तारीख को भोपाल नगर को मेट्रो की सौगात दी जाएगी। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर सरकार द्वारा लगभग दो लाख करोड़ के अलग-अलग कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2026 कृषि के संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विकास एवं उनके उत्थान के लिए समर्पित होगा। कृषि से आय के साधन बढ़ाने कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना समेत सभी कृषिगत औद्योगिक गतिविधियों से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सतत कार्य वर्षभर किये जाएंगे।

मप्र बना वाहनों की डिडुप्लीकेशन की लंबित प्रविष्टियों को शून्य करने वाला राज्य

इलेक्ट्रिक वाहनों में मोटरयान कर में पूर्ण छूट

भोपाल (नप्र)। परिवहन विभाग के प्रयासों से मध्यप्रदेश डिडुप्लीकेशन की लंबित प्रविष्टियों को शून्य करने वाला राज्य बन गया है। इस कार्यवाही का फायदा उन समस्त 2 लाख 50 हजार वाहन स्वामियों को मिला है, जो अब परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर पा रहे हैं। देश में समस्त राज्यों के परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के पंजीयन एवं उनके स्थानान्तरण के संबंध में विभिन्न परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में समय-समय पर प्रविष्टियां की जाती हैं। पूर्व में कागजों पर संधारित रिकार्ड को डिजिटाइज करने के दौरान दूसरे आरटीओ के अधिकार क्षेत्र में वाहन के स्थानांतरित होने पर पूर्व के आरटीओ द्वारा एंट्री को डिलीट न किये जाने के कारण देश में 35 लाख वाहन ऐसे थे, जिनकी प्रविष्टि एक से अधिक आरटीओ में होने से उन वाहन स्वामियों को परिवहन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस वर्ष जुलाई 2025 के अंत तक मध्यप्रदेश में करीब 2 लाख 50 हजार ऐसी प्रविष्टियां थीं। परिवहन विभाग द्वारा एक विशेष मुहिम चलाई गई। मुहिम की समीक्षा प्रत्येक पखवाड़े में परिवहन विभाग में वरिष्ठ स्तर पर किये जाने से मध्यप्रदेश में डुप्लीकेट एंट्रियों को सही कर दिया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर में पूर्ण छूट- पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत होने वाले समस्त श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर में पूर्णतः छूट प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कम्प्रेस्ड् नेचुरल गैस (सीएनजी) वाहनों पर भी राज्य सरकार द्वारा मोटरयान कर में एक प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इस प्रावधान से प्रदेश में इलेक्ट्रिक और

6 वर्षीय बच्ची का अपहरण, पैरोल पर छूटा आरोपी ले गया

बैतूल। मुलताई थाना क्षेत्र से छह वर्षीय बच्ची का अपहरण किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, गांव का ही एक युवक बच्ची को अपनी बाइक से ले गया है। आरोपी कुछ दिन पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया था। बताया जा रहा है कि आरोपी हत्या के मामले में जेल में बंद था। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि बच्ची के अपहरण की शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की तलाश के लिए 10 अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो रातभर से अभियान चला रही हैं। पुलिस ने क्षेत्र की सीमाओं पर नाकाबंदी की है और आरोपी की संभावित लोकेशन पर तलाशी जारी है। आसपास के जंगल क्षेत्रों, गांवों, संभावित ठिकानों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घटना रविवार शाम करीब

6.30 बजे सामने आई। ग्रामीणों ने अनिल कुशराम को बच्ची के साथ बाइक पर जाते देखा था। बच्ची के परिजनों को शक होने पर ग्रामीणों ने रात 11 बजे पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि आरोपी अनिल कुशराम का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह हाल ही में पैरोल पर जेल से रिहा हुआ था। इस जानकारी के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। इसके अतिरिक्त, पड़ोसी जिलों की पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि आरोपी किसी अन्य इलाके में न भाग सके। पुलिस ने जल्द ही बच्ची को सुरक्षित बरामद करने का भरोसा दिलाया है, हालांकि अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है।

पीड़ित के घर आईजी-एसपी पहुंचे- घटना की गंभीरता को देखते हुए नर्मदापुरम रेंज के आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला सोमवार को स्वयं पीड़िता के गांव पहुंचे। उनके साथ बैतूल पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन भी मौके पर मौजूद रहे। आईजी और एसपी ने परिजनों से चर्चा कर घटना की जानकारी ली और पुलिस टीमों को हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए। मुलताई और आठनेर थाना पुलिस के साथ-साथ महाराष्ट्र के वरुड, मोर्शी और बैनोडा क्षेत्र में भी सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुलताई थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार अपनी टीम के साथ वर्तमान में वरुड क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन में जुटे हैं।

पुलिस ने गुम हुए 2 करोड़ रूपए से अधिक के 944 मोबाइल खोजकर उनके मालिकों को सौंपे

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस ने नागरिकों को तकनीक-सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने और गुम मोबाइल फोन की खोज को गति देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस टीमों ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ट्रेसिंग करते हुए 2 करोड़ 13 लाख 82 हजार रूपए के कुल 944 गुम मोबाइल फोन खोजकर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द किया है। यह उपलब्धि पुलिस की तकनीकी दक्षता, त्वरित समन्वय और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है। ये सभी कार्यवाहियाँ विगत एक सप्ताह की अवधि में पूरी की गई है।

ग्वालियर- लगातार जारी अभियान से 736 मोबाइल व टैबलेट खोजे-

पुलिस ने निरंतर चल रहे तकनीकी अभियान के तहत जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि में 736 मोबाइल व टैबलेट बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंपे हैं। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 82 लाख रूपए है।

सतना- 102 मोबाइल की बरामदगी- सतना पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए सीईआईआर पोर्टल की सहायता से कुल 102 गुम मोबाइल फोन ट्रेस कर नागरिकों को लौटाए। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख 35 हजार रूपए है।

अलीराजपुर-ऑपरेशन हेलो के तहत 69 मोबाइल फोन बरामद- जिले में सायबर सेल पुलिस ने ऑपरेशन हेलो के तहत 69 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जिनकी कुल कीमत लगभग 8 लाख 97 हजार रूपए है। ये मोबाइल फोन संबंधित आवेदकों को सौंप दिए गए हैं।

मऊगंज- ऑपरेशन रिंग टोन के तहत 37 मोबाइल बरामद- मऊगंज पुलिस ने ऑपरेशन रिंग टोन के तहत 37 मोबाइल फोन, सफलतापूर्वक खोजकर आवेदकों को सौंपे है। जिनकी कुल कीमत 6 लाख 50 हजार रूपए है।

मध्यप्रदेश पुलिस की नकली नोट के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

उज्जैन व नीमच में कुल 18 लाख रूपये के नकली नोट बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस को नकली नोट के अवैध कारोबार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उज्जैन एवं नीमच पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाईयों में कुल 18 लाख रूपये के नकली नोट जब्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन कार्रवाइयों से राज्य में सक्रिय नकली नोट नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है।

उज्जैन पुलिस की कार्रवाई- थाना चिमनगंज मंडी एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 17 लाख 50 हजार रूपए के नकली 500 के नोट बरामद किए गए है। पूछताछ में उज्जैन-इंदौर के बीच सक्रिय एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है।

थाना चिमनगंज मंडी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति बड़ी मात्रा में नकली नोट लेकर उज्जैन में डिलीवरी के उद्देश्य से आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने राजरायल कॉलोनी और पांड्याखेड़ी ब्रिज क्षेत्र में घेराबंदी की। इसी दौरान ब्रिज के नीचे दो संदिग्ध युवक मिले जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा।

पकड़े गए युवको से पूछताछ करने पर

उन्होंने अपने नाम हिमांशु उर्फ चीनू गौसर निवासी गौघाट रेलवे कॉलोनी उज्जैन तथा दीपेश चौहान निवासी शिवगंगा सिटी, उज्जैन बताए। दोनों की तलाशी लेने पर हिमांशु के कब्जे से 11 लाख रूपए और दीपेश से 6 लाख 50 हजार रूपए के नकली नोट बरामद हुए। नोटों में सुरक्षा फीचर, धागा और माइक्रो प्रिंट जैसी चीज़ों की नकली कॉपी की गई थी, जिससे वे सामान्य नजर में असली प्रतीत होते थे। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इंदौर में अरविन्दो अस्पताल के सामने स्थित श्री गंगा विहार कालोनी के एक फ्लैट में अपने साथी राजेश पिता टेकचंद बरबटे के साथ मिलकर नकली नोटों की छपाई करते थे। उन्होंने बताया कि वह 10 लाख रूपए नकली नोट के बदले 1 लाख रूपए असली नोट का सौदा किया करते थे। पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ की आरोपी हिमांशु पहले भी इंदौर में नकली नोट मामले में जेल जा चुका है।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने इंदौर स्थित फ्लैट पर दबिश दी। तलाशी में नोट प्रिंटिंग मशीन, हाई-सिक्योरिटी पेपर, सुरक्षा धागा, प्रिंटिंग केमिकल, कटर मशीन तथा बड़ी मात्रा में अधपकी एवं तैयार नकली नोट शीटें बरामद की गईं। फ्लैट को पूरी तरह एक मिनी प्रिंटिंग यूनिट के रूप में तैयार किया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। आरोपियो के विरूद्ध थाना चिमनगंज मंडी में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

नीमच पुलिस की कार्रवाई- पुलिस अधीक्षक नीमच श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में नकली नोट के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नीमच सिटी की टीम को सायबर सेल की मदद से बड़ी सफलता प्राप्त हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक श्री पुष्पासिंह चौहान के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 500 रुपये के नोटों के 50 हजार रुपये मूल्य के नकली नोट जब्त कर आरोपी ईश्वर पिता वर्दीचंद खारोल निवासी ग्राम सरजना को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथी सुनिल पिता श्यामदास बैरागी निवासी ग्राम सरजना के साथ मिलकर नकली नोट छापे थे। पुलिस द्वारा दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है।

इस प्रकार पुलिस ने इन दोनों कार्रवाइयों में लगभग 18 लाख रुपये मूल्य के नकली नोट, प्रिंटिंग मशीन व अन्य सामग्री जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उज्जैन संभाग बना हर घर-जल उपलब्धि प्राप्त करने वाला प्रदेश का अग्रणी संभाग

7,09,065 ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से जल

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए जल जीवन मिशन को मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संकल्प और निरंतर प्रयासों ने नई ऊँचाई प्रदान की है। इसी का परिणाम है कि उज्जैन संभाग ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए यह सुनिश्चित कर दिया है कि यहाँ के सभी ग्रामीण घरों तक अब नल से शुद्ध पेयजल पहुँच रहा है। ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पानी का यह अधिकार निरंतर और सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो रहा है, जिससे पूरे उज्जैन संभाग को गर्व के साथ 'हर घर जल' के लक्ष्य को पूर्ण करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

इस उपलब्धि से महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक राहत मिली है। पहले गांवों की महिलाएँ दूर-दूर तक पानी लाने के लिए कठिनाई झेलती थीं, कीमती समय और श्रम दोनों व्यय होते थे। अब घर के आँगन में नल से जल उपलब्ध होने से न केवल उनका सम्मान बढ़ा है बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वच्छता और आजीविका के बेहतर अवसर भी मिले हैं। स्वच्छ पानी के कारण जलजनित बीमारियों में कमी से ग्रामीण स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार हुआ है।

उज्जैन संभाग के उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच और आगर-मालवा जिलों के कुल 7 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। आगर-मालवा 42,207, देवास 1,65,383, नीचम 31,957, उज्जैन 1,71, 553, शाजापुर 79,472, रतलाम 1,49,603 और मंदसौर 68,890 परिवार लाभान्वित हुए। यह केवल पाइपलाइन बिछाने का कार्य नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण, स्थानीय लोगों की सहभागिता और ग्रामीण जीवन को सम्मानजनक सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास है, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सक्रिय भूमिका निभाई है।

79वां होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया

विदिशा (निप्र)। होमगार्ड कार्यालय विदिशा में 79 वां होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री मुकेश टंडन रहे। विशेष अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी एवं अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर रहे। होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस स्थापना दिवस कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री मयंक कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की मुख्य झलकियां

कार्यक्रम का शुभारंभ दो होमगार्ड प्लाटून, एक आपदा मित्र दल एवं एक सिविल डिफेंस प्लाटून की आकर्षक परेड से हुआ। परेड का नेतृत्व श्री एलएन विश्वकर्मा द्वारा किया गया। सर्वप्रथम परेड ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को सलामी दी तथा तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी गई। सलामी अपरान्त मार्चपास्ट हुआ, कार्यक्रम मे मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान होमगार्ड अधिकारी, कर्मचारी एवं जवानों के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए, जिससे बच्चों में उत्साह का संचार हुआ।

सेवा सम्मान समारोह

होमगार्ड संगठन में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए अधिकारी, कर्मचारियों एवं जवानों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति-चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एसडीईआरएफ के जवानों द्वारा आपदा उपकारणों की प्रदर्शनी द्वारा लगाई गई। आधुनिक उपकरणों, बचाव साधनों एवं आपदा प्रबंधन सामग्री की प्रदर्शनी का मुख्य अतिथियों ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई तथा जवानों के कार्य एवं समर्पण की सराहना की गई।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ जवानों के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतो पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं के नृत्य एवं गीतों ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर जवानों के बच्चों की और जवानो की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई और जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिका को स्मृति-चिह्न भेंट किया गया। अतिथियों ने होमगार्ड संगठन की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि होमगार्ड सदैव आपदा, आपातकालीन परिस्थितियों एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता आया है। संगठन के सभी अधिकारी-कर्मचारियों एवं जवानों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम के अंत में प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे के द्वारा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।

आबकारी विभाग की कार्रवाई 8 स्थानों पर दबिश, अवैध मदिरा जप्त, 6 प्रकरण दर्ज

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशों के पालन में आज शनिवार को आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा पर बड़ी कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी श्री शरद पाठक के निर्देशन तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजीव थापक एवं श्रीमती साधना पटेल के नेतृत्व में वृत्त विदिशा 'ब' में संयुक्त दबिश अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम रामपुर थाना बूढ़ाखेड़ा पेगआई के टपरे,सांगुल के टपरे,अजीत पिपरिया सहित कुल 8 स्थानों पर तलाशी एवं छापामार कार्रवाई की गई।

मुख्य उपलब्धियाँ : जिला आबकारी अधिकारी श्री पाठक ने बताया कि अवैध मदिरा निर्माण एवं परिवहन से जुड़े 6 प्रकरण दर्ज किए गए।आरोपियों के कब्जे से 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, तथा 1100 किलोग्राम महुआ लाहान जप्त किया गया। जप्तशुदा सामग्री एवं उपकरणों की कुल अनुमानित कीमत लगभग एक लाख 15 हजार रुपए आँकी गई। समस्त सामग्री को आबकारी अमले द्वारा कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।दल का सराहनीय योगदान इस सफल दबिश अभियान में निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर के निर्देश पर निरीक्षणकर्ता कर रहें हैं स्कूलों एवं छात्रावासों का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार निरीक्षणकर्ता लगातार शासकीय विद्यालयों और छात्रावासों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्री संजय सिंह तोमर द्वारा जिले की 1100 से अधिक शालाओं के निरीक्षण के लिए निरीक्षणकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो निर्धारित अवधि में विद्यालयों की शैक्षणिक, भौतिक एवं प्रशासनिक स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन कर अपनी दैनिक रिपोर्ट जिला कार्यालय में जमा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी निरीक्षण दलों ने जिले के सभी विकासखंडों के स्कूलों एवं छात्रावासों का भ्रमण कर उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था, स्वच्छता, मध्याह्न भोजन, अधोसंरचना, छात्रावासीय व्यवस्थाओं सहित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का परीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षणकर्ताओं ने आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी दर्ज किए, ताकि शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। निरीक्षण अभियान 8 दिसंबर तक सतत रूप से जारी है, तथा सभी निरीक्षणकर्ताओं को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सात दिवस में सटीक एवं तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

सीहोर (निप्र)। जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीजनल एनफ्लूऐन्जा की रोकथाम, बचाव और नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि मौसम में होने वाले बदलाव के कारण सर्दी-खाँसी (इन्फ्लूएंजा) के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इस संक्रमण से बचाव के लिये व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक हैं। सीएमएचओ सुधीर डेहरिया ने बताया कि इन मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, समाजिक दूरी, मास्क पहनना आवश्यक है, ताकि संक्रमण न फैले। उन्होंने बताया कि संवेदनशील समूह जैसे छोटे बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं, लंग्स इन्फेक्शन, डायबटीज, हृदय रोग, क्रोनिक लीवर वाले मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यदि बुखार, खाँसी, तीव्र स्वशन जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि सभी आमजन स्वंय को इस बदलते मौसम में मौसमी संक्रमण से बचाव के लिये जागरूक रहें और सर्दी, खाँसी, बुखार के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में सम्पर्क कर उपचार लें।

सांसद और विधायक ने किया प्राथमिक शाला भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी ने शनिवार 06 दिसम्बर को ग्राम कोठरा, सिवनी मालवा में प्राथमिक शाला भवन के निर्माण कार्य का सिवनीमालवा विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा के साथ भूमि पूजन किया। सांसद श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री डॉ मोहन यादव के 'शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को साकार करने का यह प्रयास, गाँव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई शुरुआत करेगा। उन्होने इस अवसर पर उपस्थित ग्रामवासियों से संवाद कर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कराने हेतु सभी से आग्रह किया। इस दौरान कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमति रेणुका मृगेंद्र मंडलोई, श्री योगेन्द्र राजपूत, श्री वरुण पटेल, श्री अजीत मंडलोई, श्री जितेंद्र चौहान, ग्राम सरपंच पवन रघुवंशी एवं समस्त जनप्रतिनिधि-कार्यकर्तागण तथा ग्रामीणवासी उपस्थित रहे।

मेडिकल स्टोरों की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई, तीन संस्थानों की लाइसेंस अनुज्ञप्ति निलंबित

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में जिलेभर के मेडिकल स्टोरों की नियमित निरीक्षण कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक विदिशा द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण कमियाँ व अनियमितताएँ पाई गईं। औषधि निरीक्षक द्वारा संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को पाई गई कमियों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित अवधि में प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए।

प्राकृतिक कृषि संवर्धन विधेयक सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने सदन में किया प्रस्तावित

नर्मदापुरम (निप्र)। सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी कदम है, जिसमें केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करेगी जो सामान्य खेती में कृषि उपज के लिए निर्धारित मूल्य के दोगुने से कम नहीं होगा। इसके साथ ही समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सामान्य खेती करने वाले किसानों की तुलना में फसल बीमा का लाभ दोगुना मिले। समुचित सरकार प्राकृतिक कृषि उपज की बिक्री के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समितियों सहित सभी कृषि बाजारों में राष्ट्रीय कृषि उपज मंडी स्थापित करेगी। समुचित सरकार प्राकृतिक खेती द्वारा उगाए गए कृषि उत्पादों के भंडारण और परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करेगी। कुटीर एवं लघु उद्योगों को जैविक एवं प्राकृतिक खाद से उगाए गए कृषि उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली कम्पनियों द्वारा कार्बन क्रेडिट सीमा की खरीद से प्राप्त राजस्व का उपयोग किया जाए।

युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देने का अभियान है सांसद खेल महोत्सव : राजस्व मंत्री

सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल हुए शामिल राजस्व मंत्री

खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित

सीहोर (निप्र)। राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा इछावर तहसील में दीवाड़िया मंडल द्वारा सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित मंडल स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विजेता खिलाड़ी टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया और उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और खेल भावना को सही दिशा देने का एक बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए यह महोत्सव एक महत्वपूर्ण मंच है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी आज यहां अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, यही खिलाड़ी आगे चलकर जिले, प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल हमें अनुशासन, एकजुटता, मेहनत और सकारात्मक सोच सिखाता है। जीत-हार खेल का हिस्सा हैं, लेकिन असली जीत उस भावना की होती है जिससे हम मैदान में उतरते हैं। सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजन ग्रामीण खेल संस्कृति को मजबूत करते हैं और युवाओं को आगे बढ़ने का बड़ा अवसर प्रदान करते हैं, जिससे प्रत्येक युवा अपनी प्रतिभा को निखार सके और खेलों के माध्यम से अपना उज्ज्वल भविष्य बना सके।

शासकीय गर्ल्स कॉलेज में विद्यार्थी संसद का आयोजन हुआ

विदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा की एनएसएस इकाई द्वारा महाविद्यालय परिसर में कॉलेज पार्लियामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस विशेष गतिविधि का उद्देश्य छात्राओं को व्यावहारिक रूप से संसद की कार्यप्रणाली से परिचित कराना एवं ससंद के कार्यों को समझाना था। कॉलेज पार्लियामेंट में छात्राओं ने प्रश्नकाल, शून्यकाल तथा विधेयक प्रस्तुति जैसी संसदीय प्रक्रियाओं का सजीव प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एनएसएस स्वयं सेविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं की गहन समझ विकसित की। कार्यक्रम महाविद्यालय प्राचार्य एवं संरक्षक डॉ. बीडी अहिरवार के निर्देशन में संपन्न हुआ।

प्राचार्य ने सभी छात्राओं के इस कार्य की सराहना की एवं शुभकामना देते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह के आयोजन करने की सीख दी। मंच संचालन का दायित्व अतिथि विद्वान नीतु दांगी ने प्रभावशाली रूप से निभाया तथा कार्यक्रम का मार्गदर्शन एवं संयोजन अतिथि विद्वान डॉ. शांता अहिरवार द्वारा किया गया। एनएसएस की सभी छात्राओं के सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता से यह कार्यक्रम अत्यंत सफल एवं प्रभावी सिद्ध हुआ। महाविद्यालय प्रशासन ने इस शैक्षणिक एवं प्रेरक पहल की सराहना करते हुए आगे भी ऐसे गतिविधि-आधारित शिक्षण कार्यक्रमों को करने की बात कही।

हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित

नर्मदापुरम (निप्र)। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन÷ के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ललित डेहरिया के मार्गदर्शन में वन स्टॉप सेंटर नर्मदपुरम द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन 16 दिवसीय विशेष अभियान के तहत नर्मदा विद्या निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशासक प्रतिभा बाजपेयी ने छात्र छात्राओं को महिला हेल्पलाइन181, घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम?2005, पोस्को अधिनियम?2012 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन1098 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर्व शिक्षा अभियान के ब्रांड एंबेसडर डॉ. मयंक तोमर ने साइबर क्राइम और जेंडर समानता पर प्रकाश डाला। काउंसलर भागवती विष्ट ने गुड टच, बैड टच तथा वन स्टॉप सेंटर की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। स्कूल संचालक स्वपनिल उपाध्याय ने बालिकाओं को उनके अधिकार, सुरक्षा और करियर के अवसरों के विषय में जागरूक किया। प्राचार्य अनुज दीवान ने सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन स्कूल की शिक्षिका कनिष्का गौर ने किया तथा कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर से केसवर्कर पूजा खरवार, आईटी वर्कर रजनी श्रोती, स्कूल शिक्षिकाएँ तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे।

मछुआरों के किसान क्रेडिट कार्ड हेतु शिविर का आयोजन

विदिशा (निप्र)। मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले की नदियों में मत्स्याखेट कार्य में संलग्न मछुआरों को वित्तीय सहायता एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर शनिवार अवकाश दिवस को गंजबासौदा के केवट धर्मशाला में आयोजित किया गया था। शिविर का शुभारंभ विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि केसीसी के माध्यम से मछुआरों को जाल, नौका मरम्मत, इंजन, फिशिंग उपकरण, चारा सामग्री तथा अन्य मत्स्याखेट गतिविधियों के संचालन हेतु अल्प ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शिविर के दौरान विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने स्थल पर ही मछुआरों के दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा पात्र मछुआरों के आवेदन फार्मों को भरवाया। अनेक मछुआरों ने मौके पर ही अपने आवेदन जमा किए। विभाग ने बताया कि प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से बैंक स्तर पर भेजकर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मछुआरों ने विभाग द्वारा आयोजित इस पहल से मौके पर लाभान्वित होने कहा कि केसीसी उपलब्ध होने से उन्हें मत्स्याखेट कार्य में आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी और आजीविका सुचारू रूप से चल सकेगी। मछली पालन विभाग, विदिशा द्वारा आगामी दिनों में भी इसी प्रकार के जनहितकारी शिविर आयोजित किए जाने की योजना है, ताकि अधिक से अधिक मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिलाया जा सके।

खाद वितरण सोसायटी केंद्र सागुल का निरीक्षण

विदिशा (निप्र)। शमशाबाद के तहसीलदार डॉ. दर्शन सिंह नेगी ने आज खाद वितरण सोसायटी केंद्र सागुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वितरण व्यवस्था, स्टॉक पंजी, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही खाद की मात्रा, पारदर्शिता तथा व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन किया। तहसीलदार ने केंद्र में उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि किसानों को समय पर एवं निर्धारित मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या देरी न हो।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किया गया 580 बच्चों का टीकाकरण

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। जिले में 05 दिसंबर को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 415 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 165 बच्चों का टीकाकरण किया गया।

विशेष समाचार - आष्टाङ्करानीपुरा जल परियोजना - सीहोर के गाँवों में विकास की नई धारा

सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले में ग्रामीण जीवन को बदलने वाली आष्टाङ्करानीपुरा समूह जल प्रदाय परियोजना आज एक मील का पत्थर बनने जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत 1478 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही यह परियोजना केवल एक विकास कार्य नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने वाला सशक्त माध्यम है। सुरक्षित पेयजल की कमी से परेशान सैकड़ों गांवों के लिए यह योजना उम्मीद की ऐसी किरण बनी है, जिसने क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 719 गांवों के 91,972 परिवारों तक नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है और प्रशासन की दृढ़ता तथा सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज इस परियोजना की कुल भौतिक प्रगति

62 प्रतिशत हो चुकी है। इंटेक वॉल का 65त्न, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 70त्न, तथा 245 में से 175 ओवरहेड टैंक पूर्ण हो चुके हैं। 05 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशनों में से 3 का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जबकि 4,625 किमी लंबी पाइपलाइन में से 2,225 किमी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। यह गति सिद्ध करती है कि यह परियोजना किस तरह एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी कार्यप्रणाली के साथ आगे बढ़ रही है। इस परियोजना के पीछे केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक नेतृत्व और जनसहभागिता का शानदार समन्वय भी है। मध्यप्रदेश जल निगम, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सतत निरीक्षण एवं मार्गदर्शन ने परियोजना को मज़बूत आधार प्रदान किया है। वहीं ग्राम स्तर पर जल समितियों की सक्रिय भागीदारी ने इस योजना को स्थायी और सामुदायिक स्वरूप दिया है। परियोजना के पूर्ण होने पर आष्टाङ्करानीपुरा क्षेत्र के गांवों में हर घर नल से जल पहुँचने लगेगा। इससे महिलाओं और बच्चों को पानी लाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, जलजनित रोगों में कमी आएगी, स्कूली शिक्षा में नियमितता बढ़ेगी और स्वास्थ्य स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह योजना सिर्फ पेयजल उपलब्ध कराने की पहल नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक परिवर्तन लाने वाला सामाजिक आर्थिक सुधार भी है। आष्टाङ्करानीपुरा समूह जल प्रदाय परियोजना इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार की नीतियाँ, प्रशासन की कार्यकुशलता और जनता की सहभागिता एक साथ काम करती है, तब बदलाव केवल कागज़ पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर दिखाई देता है। यह परियोजना आने वाले समय में सीहोर जिले की सबसे प्रेरक परियोजना के रूप में याद की जाएगी–एक ऐसी परियोजना जिसने हजारों परिवारों के जीवन में स्वच्छ जल की धारा के साथ उम्मीद, स्वास्थ्य और विकास की नई शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बसों को दिखाई हरी झंडी

एक साथ 19 पर्यटक ले सकेंगे अब जंगल सफारी का आनंद

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार सुबह पन्ना नेशनल पार्क के मडला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इन बसों के जरिए पर्यटक जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव और अधिक सुविधाजनक तरीके से ले सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा हैं।

मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को एक और सौगात देते हुए प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम उठाया है। जंगल सफारी के लिए 10 नई आरामदायक वीविंग कैंटर बसें उपलब्ध करायी हैं। इन कैंटर बसों में एक साथ 19 पर्यटकों के बैठने की क्षमता है। यह बसें अन्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची हैं, जिससे पर्यटकों को बेहतर दृश्य और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बसें अधिक सुरक्षित मानी जा रही हैं। इन बसों की लंबाई और ऊंचाई भी अधिक है, जिससे सफर के दौरान पर्यटकों को ज्यादा जगह और आराम मिलता है। वहीं बच्चों और सीनियर सिटिज़न्स के लिए यह बसें सुरक्षित और अनूठा अनुभव प्रदान करेंगी। इन बसों में बैठकर पर्यटक न केवल वन्यजीवों के विचरण का नज़ारा देख सकेंगे।

ऑनलाइन बुकिंग न होने पर पर्यटकों को मिलेगी पार्क राउंड की सुविधा

10 नई वीविंग कैंटर बसों के संचालन से उन पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग न होने पर भी जंगल सफारी के आनंद और अनुभव से वंचित नहीं होंगे।

ऑनलाइन स्लॉट जल्दी भर जाने से पर्यटकों को नेशनल पार्क पहुंचकर भी सफारी से वंचित होने जैसी असुविधा अब नहीं होगी।

एंट्री गेट से ही बुकिंग की सुविधा

नई कैंटर बसों के संचालन के बाद अब पर्यटकों को नेशनल पार्क के गेट पर ही सफारी बुक करने की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन वाहनों से जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति/प्रति राउंड लगभग 1150 से 1450 रुपए तक शुल्क देना होगा।

ये 10 नई कैंटर बसें प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्कों और पर्यटन स्थलों जैसे बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, परसिली (सीधी) सहित अन्य नेशनल पार्क्स और अन्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुविधा के लिए संचालित की जाएंगी।

कर्ज में डूबी एमपी सरकार प्रॉपर्टी बेचकर भरेगी खजाना

केरल से मुंबई तक बिकेगी करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति, केंद्र से भी प्रॉपर्टी लेने की तैयारी

भोपाल (नप्र)। 4 लाख 64 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी मध्यप्रदेश सरकार अब इससे उबरने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए देश के दूसरे राज्यों में मौजूद एमपी के अलग-अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी है।

वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है, जिसमें पूछा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है? उसका

मूल्य क्या है? अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी तरह का विवाद है तो इसकी भी जानकारी दी जाए।

मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इन जानकारियों के आधार पर लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग पूरे देश में फैली इन संपत्तियों का व्यापक डेटाबेस तैयार कर रहा है। इस कवायद का मकसद प्रदेश के बाहर मौजूद संपत्ति को बेचकर या किराये पर देकर राशि जुटाना है। यह विभाग इन संपत्तियों के मुद्रीकरण यानी मॉनेटाइजेशन की रणनीति बनाएगा। केरल के वायनाड से लेकर मुंबई के पॉश इलाकों और उत्तर प्रदेश के झांसी तक, मध्य प्रदेश सरकार की करोड़ों-अरबों की संपत्तियां हैं, जो या तो विवादों में फंसी हैं या उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है।

सौदा तैयार, कैबिनेट की मुहर का इंतजार

मध्य प्रदेश सरकार की कंपनी, प्रोविडेंट इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के अधिकार में केरल के वायनाड जिले में 554.05 एकड़ की विशाल बीनाची एस्टेट है। इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा (453.96 एकड़) केरल प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट, 1971 के तहत केरल सरकार के अधीन कर दिया गया था, जिसके खिलाफ पीआईसीएल ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

लंबे चले इस विवाद के बाद, 3 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। 12 फरवरी 2021 को हुई अंतिम बैठक में यह तय हुआ कि- बीनाची एस्टेट को एक उचित मुआवजे के आधार पर केरल सरकार को सौंप दिया जाएगा। मुआवजे की राशि दोनों राज्यों के अधिकारी मिलकर तय करेंगे, और सहमति न बनने पर एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। संपत्ति सौंपने के बाद केरल सरकार वहां बसे 160 अतिक्रमणकारी परिवारों को भूमि आवंटित करने पर विचार करेगी।

शुभम गोस्वामी से अमन खान बने युवक की घर वापसी

मुस्लिम युवती के प्यार में बदला था धर्म, मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में हुआ शुद्धिकरण

भोपाल (नप्र)। जहांगीराबाद में रहने वाले शुभम गोस्वामी ने सोमवार को धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर ली। उन्होंने कुछ समय पहले एक मुस्लिम युवती के प्यार में धर्म बदल लिया था, लेकिन कथित धोखे और दबाव के बाद उन्होंने वापस सनातन धर्म अपनाने का निर्णय लिया।

गुफा मंदिर में हवन, उपनयन संस्कार, गुरुदीक्षा, मुंडन, गोपूजन और गंगाजल से शुद्धिकरण की विधि कराई गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे।शुभम का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के बाद उसे अमन खान नाम अपनाने को मजबूर किया गया था। रामप्रवेश दास देवाचार्य महाराज ने बताया- अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश सनातन धर्म से दूर चला जाए तो पुनः लौटने की सामान्य प्रक्रिया है। मुंडन, कंठी-तुलसी धारण, तिलक, गोपूजन, हवन आदि संस्कार किए जाते हैं।

मंत्री विश्वास सारंग के जनदर्शन में पहुंचा था युवक- शुभम ने 29 नवंबर को मंत्री सारंग के जनदर्शन में पहुंचकर अपनी कहानी बताई थी। मंत्री के अनुसार, युवक ने आरोप लगाया कि दबाव डालकर मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा गया, प्रेम-जाल में फंसाया गया, गोमांस खिलाया गया और जमात में भेजा गया। मंत्री ने कहा कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और तीन आरोपी जेल में हैं।

चार महीने तक इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार रहा

शुभम ने कहा कि वह नॉन-वेज खाता था, नमाज पढ़ता था, मस्जिदों में रहता था, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो उसने मदद मांगी। कार्रवाई के बाद उसने हिंदू धर्म वापस अपनाया।युवक के मुंडन, कंठी-तुलसी धारण, तिलक, गोपूजन, हवन आदि संस्कार कराए गए।

2022 में हुई थी पहचान, बाद में बढ़ा दबाव

शुभम के मुताबिक, 2022 के अंत में शुभम की एक मुस्लिम युवती से पहचान हुई। शुरुआत में सब सामान्य रहा। बाद में उसके परिवार ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू किया। झूठे केस दर्ज कराए गए, वह जेल भी गया। धमकियां दी गईं कि हिंदू धर्म नहीं छोड़ा तो परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

तीन साल अपने घर से दूर मुस्लिम मोहल्ले में रहा

युवक ने कहा कि सबसे बड़ा दबाव अपनी पहचान खोने का था। उन्होंने कहा कि अब तुम शुभम नहीं, अमन खान हो। मजबूरी में मुझे वही नाम बताना पड़ता था। शुभम के मुताबिक, वह तीन साल अपने घर से दूर मुस्लिम मोहल्ले में रहा। युवक ने कहा कि मैंने परिवार से रिश्ता लगभग खत्म कर दिया था। नौकरी भी छूट गई।

महेश्वर में सात घंटे से किसानों का चक्काजाम

बोले- दिन में 10 घंटे बिजली दी जाए, विधायक को बुलाने की मांग पर अड़े

महेश्वर (नप्र)। महेश्वर तहसील के किसानों ने सिंचाई के लिए रात में मिल रही बिजली आपूर्ति के विरोध में सोमवार को बड़वाह-धामनोद मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। यह प्रदर्शन धरगांव के भार्गव स्थित उमिया माता गेट पर सुबह 11 बजे शुरू हुआ। किसान दिन में 10 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। किसान विधायक राजकुमार मेव को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे है।

किसानों ने चेतावनी दी है कि रात्रि में सिंचाई के दौरान किसी भी अनहोनी की पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और विद्युत मंडल की होगी। सैकड़ों किसानों ने सड़क पर बैठकर विद्युत मंडल और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस चक्काजाम के कारण मुख्य मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया।

दिन में 10 घंटे बिजली की मांग पर अड़े किसान

किसानों की मुख्य मांग है कि सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति तत्काल दिन में 10 घंटे की जाए। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में खेतों में सिंचाई करना बेहद खतरनाक होता है। रात में जंगली जानवरों, सर्पदंश और अन्य दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा बना रहता है।

इन जोखिमों के कारण किसान अपनी फसलों को पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उनकी पैदावार और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एक किसान प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग है कि वर्तमान में मिल रही अपर्याप्त आपूर्ति को बढ़ाकर दिन में 10 घंटे किया जाए और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, चक्काजाम जारी रहेगा।

धरना स्थल पर पुलिस-प्रशासन मौजूद

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना प्रभारी दीपक यादव, तहसीलदार कैलाश सस्त्या और एमपीईबी (विद्युत विभाग) के वरिष्ठ अधिकारी भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। अधिकारी किसानों से बातचीत कर रास्ता खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।

लंबा जाम अभी भी बना हुआ है। प्रशासन किसानों को समझाने में जुटा है, लेकिन किसान किसान एकता जिंदाबाद और जय जवान, जय किसान के नारे लगाते हुए डटे हुए हैं। किसान प्रतिनिधियों ने साफ ऐलान कर दिया है कि चक्का जाम फिलहाल जारी रहेगा। उनका कहना है कि प्रशासन की किसी भी बात को तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक उनकी मागें पूरी नहीं हो जातीं।

सांसद-विधायक न आए तो अर्धनग्न प्रदर्शन की चेतावनी

किसानों ने कहा कि यदि सांसद और विधायक मौके पर नहीं पहुंचते हैं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों का दावा है कि वे अर्धनग्न होकर भी धरना देंगे, लेकिन प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। किसानों ने दो टूक कहा कि जब तक सांसद और विधायक स्वयं मौके पर आकर उनसे बातचीत नहीं करते, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।

पहली बार नर्मदा पर बनेगी 7 किमी लंबी पेंटिंग

मंत्री प्रहलाद की बेटी करेगी दो साल की नर्मदा यात्रा डूबे हुए तपस्थल भी दिखेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की बेटी प्रतिज्ञा सिंह पटेल 1330 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करने जा रहीं हैं। प्रतिज्ञा की यह यात्रा परिक्रमा करने वाले दूसरे यात्रियों से अलग होगी। प्रतिज्ञा करीब दो साल में नर्मदा परिक्रमा पूरी करेंगी।

15 दिसंबर को अमरकंटक से प्रतिज्ञा की यात्रा शुरू होगी। इस मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके परिजन मौजूद रहेंगे।

7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग बनाएंगी

प्रतिज्ञा पटेल अमरकंटक से लेकर नर्मदा नदी के अरब सागर तक के सफर का चित्रांकन करेंगी।1330 किलोमीटर की इस यात्रा में नदी के दोनों किनारों के दृश्यों की पेंटिंग बनाएंगी।

हर 150 किलोमीटर के दृश्य एक किलोमीटर की पेंटिंग पर उकेरे जाएंगे। अमरकंटक, ओंकारेश्वर जैसे कुछ स्थानों के चित्रण में करीब डेढ़ से दो किलोमीटर की पेंटिंग हो सकती है। इस तरह 1330 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा को सात किलोमीटर की पेंटिंग में बनाने की तैयारी है।

डूब में आए स्थल भी पेंटिंग में दिखेंगे

प्रतिज्ञा कहतीं हैं कि मेरे माता-पिता, चाचा, मामा-मामी नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। पापा ने 1994 में पहली नर्मदा परिक्रमा की थी। इसके बाद 2005 में पापा और मम्मी दोनों ने साथ में नर्मदा परिक्रमा की थी। पापा (प्रहलाद पटेल) के पास नर्मदा परिक्रमा की 52 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसके आधार पर मैं अपनी पेंटिंग्स में यह दिखाऊंगी कि 1994 में नर्मदा किनारे कौन से तप स्थल कहां कैसे दिखते थे। 2005 में कहां कैसे दृश्य थे।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

नई गाइड लाइन और निशाने पर मंत्री ओ पी चौधरी

छत्तीसगढ़ की सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में बाजार मूल्य और जमीन रजिस्ट्री की दरें एक सामान हो गई हैं, पर इस बदलाव से रजिस्ट्री दरें 500 से 800 फीसदी उछल गई हैं। बताते हैं कुछ जगहों पर रजिस्ट्री दरें 1000 से ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे जमीन के कारोबारी, बिल्डर और आम लोग उत्तेजित हैं। दुर्ग और अन्य जगह पर जमीन कारोबारियों ने मंत्री ओ पी चौधरी का पुतला जलाया और सड़क भी जाम किया। नई गाइडलाइन से राज्य में जमीन का कारोबार एक तरह से ठप्प पड़ गया। मंत्री ओ पी चौधरी पंजीयन मंत्री हैं, इस कारण जवाब भी वही दे रहे हैं और लोगों के गुस्से के शिकार भी। आमतौर पर जमीन रजिस्ट्री गाइडलाइन हर साल कुछ न कुछ बढ़ता है, जिससे सरकार के राजस्व में कुछ वृद्धि हो, पर हवाई जहाज की स्पीड से पहली बार बढ़ा है। इसे लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। जमीन में कच्चे और पक्के का खेल सालों से चला आ रहा है। इसे एक दिन या एक झटके में बंद नहीं किया जा सकता। इसे सरकार को समझना होगा। इस मुद्दे में कांग्रेस अलाव में आग तापने का काम जरूर कर रही है, पर सरकार को हिला नहीं पा रही है। इस मुद्दे में भाजपा का एक तबका जमीन कारोबारियों के साथ हैं,क्योंकि नेतागीरी के साथ जमीन के कारोबार में भी हाथ आजमाते हैं। अब देखते हैं लोगों के उबाल के सामने सरकार कदम पीछे खींचती हैं या अपने फैसले पर अडिग रहती है। वैसे बिजली छूट के मुद्दे पर सरकार 100 से 200 यूनिट की,तो लोगों को आस है नई गाइडलाइन मुद्दे में भी कुछ राहत मिलेगी।

विधायक जी ने बनाई नई कंपनी

चर्चा है कि भाजपा के एक विधायक जी ने अपने रिश्तेदार के नाम से एक प्रचार एजेंसी बनाई है और सरकारी संस्थाओं के प्रचार-प्रसार का काम लेना शुरू कर दिया है। बताते हैं पहली बार के विधायक जी जमीनी नेता नहीं हैं। भाजपा की लहर में जीत गए और टिकट भी फेस वेल्यू पर मिल गया। खबर है कि भाजपा के जमीनी नेता अबकी बार विधायक जी को उनकी जमीन दिखाने की ठान ली है। विधायक जी के बारे में हल्ला है कि वे अपने विधानसभा में गदर मचा के रखे हैं। कुछ फैक्टरियों में अपनी गाड़ी लगवा ली है, तो कुछ के साथ महीने की डीलिंग कर ली है। वैसे भी विधायक जी जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के जनप्रतिनिधि में यह अवगुण तो आ ही जाता है, फिर फर्स्ट एंड लास्ट में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। भाजपा के नए-नवेले विधायक जी भी शायद अपने पूर्ववर्तियों का अनुशरण कर रहे हैं।

पांच कलेक्टरों के तबादले का प्रस्ताव

खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पांच कलेक्टरों के तबादले का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है। राज्य में एस आई आर के चलते के सरकार को कलेक्टरों के तबादले के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। चर्चा है कि सरकार ने जिन पांच कलेक्टरों के तबादले का प्रस्ताव भेजा है, उनमें एक दुर्ग संभाग, एक रायपुर संभाग, एक बिलासपुर संभाग, एक बस्तर संभाग और एक सरगुजा सभाग में कलेक्टर हैं। कलेक्टरों के तबादले के प्रस्ताव के साथ कोरबा कलेक्टर का मामला सुर्ख़ियों में आ गया है। पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर राज्य के मुख्य सचिव विकासशील से मिले थे। सुनने में आ रहा है कि कंवर ने चीफ सेक्रेटरी से कलेक्टर की शिकायत की और कोरबा कलेक्टर को बदलने की मांग की। अब देखते हैं ननकीराम की बात कितनी सुनी जाती है।

सचिव साहब की भभकी

कहते हैं कि राज्य के एक सचिव साहब अपने मातहतों को गीदड़ भभकी देने के लिए चर्चित हो चले हैं। बताते हैं सचिव साहबअपने मातहतों को कभी सीबीआई का डर दिखाते हैं तो कभी ईडी का।सचिव साहब अपने को बड़े पाक-साफ़ और ईमानदार बताते हैं। सचिव साहब जब कलेक्टर थे, तब सुर्ख़ियों में आए थे और तब उनके वरिष्ठ अफसर ने उन्हें नोटिस भी थमा दिया था। समय-समय की बात है। अब वे वरिष्ठ हो गए तो शेर बन गए और अपने मातहतों को गुर्राने लगे हैं। सचिव साहब की भभकियों से परेशान कुछ महिला अफसरों ने अपना विभाग ही बदलवा लिया और उनसे मुक्ति पा ली। चर्चा है कि सचिव महोदय की आदत से मातहत काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और विभाग रसातल में जा रहा है, जबकि सरकार ने तेजतर्रार छवि के चलते उन्हें विभाग में जान फूंकने और ऊंचाई में पहुँचाने के लिए पदस्थ किया है।

ओएसडी ने मंत्री जी को लगा दी चपत

खबर है कि ओएसडी साहब ने राज्य के एक मंत्री महोदय को लंबी चपत लगा दी। चर्चा है कि एक काम के बदले करोड़ों के डील में मंत्री महोदय को 25 फीसदी ही मिला। ओएसडी साहब 75 फीसदी हिस्सा डकार गए। बताते हैं कि ओएसडी साहब मंत्री जी के बड़े भरोसे के आदमी थे। मंत्री जी सभी तरह के काम धाम ओएसडी के मार्फ़त ही करवाते थे। सुनने में आ रहा है कि ओएसडी साहब मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और दोनों की जान-पहचान काफी पुरानी है। मंत्री जी पहली बार विधायक बने हैं, पर विधायक बनने से पहले सत्ता के कई घाट का पानी पी चुके हैं। पर इस मामले में मंत्री जी को न तो कुछ बोलते बन रहा है और न ही सहन कर पा रहे हैं। भाजपा के भीतर इस घटना का चटखारे लिया जा रहा है।

मंत्री जी का नया पैतरा

चर्चा है कि राज्य के एक मंत्री जी ने विभाग में ठेके और अन्य कामों में वसूली के लिए नया पैतरा अपनाया है। बाकायदा इसके लिए अपने दो विश्वसनीय लोगों की विभाग में पोस्टिंग करवाई है। दोनों विश्वसनीय मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। बताते हैं मंत्री जी के विश्वसनीय लोग दूसरे फील्ड में महारत रखते हैं, पर उन्हें ऐसा काम दे दिया गया है, जिसके बारे में वे जानते ही नहीं हैं। अब मंत्री जी का फरमान है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पर कानाफूसी तो चल ही रही है। खबर है कि मंत्री जी के विश्वसनीय लोगों का काम विभाग में चल रहे कामों को देखना और मंत्री जी के लिए उचित व्यवस्था करवाना है। अब देखते हैं यह व्यवस्था कितने दिन तक चलती है। बताते हैं मंत्री जी अपनी जेब गर्म करने के लिए पहले अपने एक निज सचिव पर निर्भर रहते थे। अब नया रास्ता अपनाया है।

बहती गंगा में डुबकी की कोशिश

कहते हैं एक अध्यक्ष महोदय धान खरीदी के मौसम में अपना भी कुछ भला कर लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय जिस संस्था के प्रमुख हैं, उस संस्था की प्रदेश इकाई से लेकर गांव-गांव तक धान खरीदी में सक्रिय भूमिका निभाता है। संस्था धान खरीदी के नाम पर नापतौल उपकरण से लेकर अन्य सामानों की व्यवस्था भी करती है। चर्चा है कि अध्यक्ष महोदय अपने कुछ अफसरों को इस खरीदी में हिस्सेदारी के काम में लगा दिया है। बताते हैं अध्यक्ष काम की मॉनिटरिंग में भी लगे हैं।